।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

● वर्ष-5
● अंक-211
रायपुर, मंगलवार
21 अप्रैल 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› रामअवतार जग्गी हत्याकांड में ...

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संस्कृत को राष्ट्र की आत्मा बताया

■ कहा- लोगों को सीखनी चाहिए यह भाषा

नईदिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को संस्कृत सीखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इसे भारत की आत्मा और देश की सभ्यतागत निरंतरता के लिए जरूरी तत्व बताया। वे दिल्ली में संस्कृत भारती के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। संस्कृत भारती एक ऐसी संस्था है जो संस्कृत को एक जीवंत और व्यापक रूप से प्रयुक्त भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम में संस्कृत को आधुनिक संचार माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा,% संस्कृत एक भाषा है। फिर भी, यह मात्र एक भाषा नहीं है। भारत में, संस्कृत राष्ट्र की आत्मा है क्योंकि यह विचार, जीवन और संस्कृति की सबसे प्राचीन परंपरा है – एक ऐसी परंपरा जो आज भी जीवंत है – जो भारत में विद्यमान है।% उन्होंने भारत के दार्शनिक विचार को और विस्तार से समझाते हुए कहा,% भारत का अस्तित्व मात्र एक भौगोलिक तथ्य नहीं है। यह महज एक राजनीतिक या आर्थिक इकाई नहीं है। भारत एक जीवंत परंपरा है– वह आधारशिला जिस पर जीवन की निरंतरता टिकी हुई है।%

भाषा के साथ अपने अनुभवों पर विचार करते हुए, भागवत ने कहा, %बचपन में जब स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, तो यह कठिन लगती थी। पाठ्यक्रम में श्लोकों को याद करना अनिवार्य था, जिससे यह धारणा बनी कि

संस्कृत एक कठिन भाषा है। फिर भी, जब मैंने उन्हीं श्लोकों को घर पर स्वाभाविक रूप से बोलते हुए सुना, तो वे मुझे कभी भी कठिन नहीं लगे।% उन्होंने आगे कहा यह समस्या आज भी बनी हुई है। छात्र संस्कृत को एक कठिन भाषा मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह इतनी कठिन क्यों लगती है? वास्तव में, किसी भाषा को सीखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से नहीं, बल्कि बातचीत के माध्यम से है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषा सीखने का सबसे आसान तरीका उसमें पूरी तरह डूब जाना और नियमित रूप से उसका उपयोग करना है। उन्होंने कहा जब भी मैं भारत भर में यात्रा करता हूं, भले ही मुझे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की विशिष्ट शब्दावली का ज्ञान न हो, फिर भी मैं भाव और अर्थ को समझ पाता हूं। निरंतर सुनने और बोलने से भाषा सहजतापूर्वक और बिना किसी प्रयास के सीखी जा सकती है। इसलिए, भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच रहें, उन्हें सुनें और लगातार उस भाषा को बोलें%

उन्होंने आगे कहा कि पिछले 15 वर्षों में संस्कृत के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में आया परिवर्तनकारी बदलाव साफ रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने पाया कि बदलती परिस्थितियां लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से फिर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। ऐसे संदर्भ में, संस्कृत सीखने और समझने के अवसर प्रदान करना एक महत्वपूर्ण मिशन बन जाता है। भागवत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा नए कार्यालय का निर्माण नि:संदेह खुशी और उत्साह का स्रोत है; हालांकि, हमें यह समझना होगा कि कार्यालय स्वयं कार्य का कारण नहीं है, बल्कि कार्य के विस्तार का परिणाम है।

आज जर्मनी दौरे पर जाएंगे राजनाथ सिंह

चीन की बढ़ेगी टेंशन! 99,000 करोड़ की सबमरीन डील पर लगेगी मुहर?

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल से शुरू होने वाले तीन दिवसीय जर्मनी दौरे पर रहेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य नई दिल्ली और बर्लिन के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। इस दौरे के दौरान राजनाथ सिंह अपने जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस और अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत करेंगे। सात वर्षों में यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय रक्षा मंत्री जर्मनी का दौरा करेगा। इससे पहले, निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2019 में जर्मनी का दौरा किया था।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजनाथ सिंह के इस दौरे से दोनों देशों के

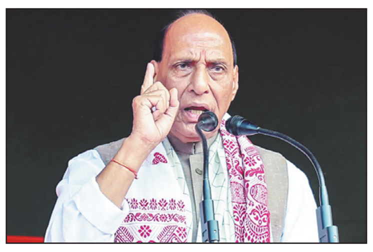

रक्षा उद्योगों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चर्चा में रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, सैन्य-से-सैन्य संबंधों को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में अवसरों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

बयान में आगे कहा गया कि दोनों रक्षा मंत्रियों की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियानों के प्रशिक्षण में सहयोग हेतु एक रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप और कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। राजनाथ सिंह की जर्मनी यात्रा के दौरान, भारत और जर्मनी के बीच भारतीय नौसेना के लिए छह उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों (प्रोजेक्ट 75आई) के सौदे पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। यह सौदा 70,000 करोड़ रुपये से 99,000 करोड़ रुपये के बीच होने की उम्मीद है, जिसके तहत इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स के सहयोग से किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75आई के तहत आने वाली ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की जलमग्न क्षमताओं को और मजबूत करेंगी। पनडुब्बी सौदे के अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), साइबर सुरक्षा और ड्रोन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों देश रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोडमैप पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष की पीएम मोदी को सीधी चुनौती-

देश से झूठ बोलना बंद करें अभी दें महिला आरक्षण

नईदिल्ली। शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कन्या भ्रूण हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए उन्हें हताश बताया। खरगे ने साफ तौर पर कहा कि इसे राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के आरक्षण के उपाय के रूप में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं है।

खरगे ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कुछ भी सार्थक न कर पाने वाले हताश और निराश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने आधिकारिक संबोधन को कीचड़ उछालने और सरासर झूठ से भरे राजनीतिक भाषण में बदल दिया। आचार संहिता पहले से ही लागू है और यह स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कैसे किया। यह लोकतंत्र और भारत के संविधान का घोर अपमान है।

उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कांग्रेस का 59 बार जिक्र किया और महिलाओं का केवल कुछ ही बार। इससे देश को उनकी प्राथमिकताओं के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। महिलाएं भाजपा की प्राथमिकता नहीं हैं। कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस इतिहास के सही पक्ष में खड़ी है। कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है। हम वह पार्टी थे जिसने 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण

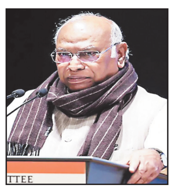

विधेयक पारित कराया ताकि वह निरस्त न हो जाए। भाजपा उस विधेयक को लोकसभा में पारित नहीं करा सकी। उन्होंने 2023 में एक और विधेयक लाया और कांग्रेस पार्टी ने उसका भी समर्थन किया। खरगे ने कहा कि वह विधेयक अभी भी लागू है। दरअसल, इसे 16 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था, जब लोकसभा परिसीमन संबंधी संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर चर्चा कर रही थी। यह कार्य उसी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। भाजपा को अपना विधेयक अधिसूचित करने में तीन साल लग जाना, भारत की नारी शक्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है! उन्होंने कहा कि मोदी जी को देश से झूठ बोलना बंद करना चाहिए — उन्हें 2023 के कानून के तहत मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में महिलाओं के लिए 33त्न आरक्षण लागू करना चाहिए। महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व अभी न दें। उन्होंने कहा कि परिसीमन विधेयकों, यानी तीन संविधान संशोधन विधेयकों को महिला आरक्षण विधेयक के साथ न मिलाएं। देश से यह झूठ बोलना बंद करें कि यह महिला आरक्षण विधेयक — नारी शक्ति वंदन अधिनियम — में संशोधन था। ऐसा नहीं है। यह पूरी तरह से परिसीमन विधेयक था, जिसे और अधिक विभाजन पैदा करने और चुनावी मानचित्र को इस तरह से बदलने के लिए लाया गया था जिससे केवल भाजपा को ही फायदा हो।

कोरिया के राष्ट्रपति ली और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने भारत-कोरिया बिजनेस लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कार्यक्रम में मौजूद उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ समूह फोटो खिंचवाई। साथ ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति ली ने सेल्फी ली।

उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की दो-दिवसीय यात्रा

नईदिल्ली। राष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने अपनी दो दिवसीय श्रीलंका यात्रा के दौरान सोमवार को नुवारा एलिया के केंद्रीय चाय बागान जिले में भारत की सहायता से निर्मित घरों के भारतीय मूल के तमिल लाभार्थियों से मुलाकात की। यह किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली यात्रा है। उन्होंने इस दौरान भारत सरकार और लोगों की श्रीलंका में तमिल समुदाय के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दोहराई। राधाकृष्णन ने इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उपराष्ट्रपति ने बताया कि भारत सरकार ने अब तक श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के साथ-साथ बागान क्षेत्रों में भारतीय मूल के तमिल परिवारों के लिए 50,000 घर उपलब्ध कराए हैं। भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के तहत 10,000 और घर दिए जाएंगे। इस परियोजना की कुल प्रतिबद्धता लगभग 1,835 करोड़ रुपये है।

प्रमुख समाचार

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा! भाजपा ने आग लगाई है : राहुल

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मणिपुर में तनाव को लेकर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि उन्होंने ही आग लगाई है। उन्होंने सत्तारूढ़ दल को मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष के लिए जिम्मेदार ठहराया। कोलाचेल में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि

मणिपुर में जो हुआ उसे देखिए। एक शांतिपूर्ण राज्य। उन्होंने आग लगा दी और सैकड़ों लोग मारे गए। वहां अभी भी गृहयुद्ध जारी है। राहुल गांधी की ये टिप्पणी मणिपुर में नए सिरे से तनाव के बाद आई है, जो ट्रोंगलाओबी अवांग लेइकाई में एक आतंकवादी हमले में 5 वर्षीय लड़के और उसकी 5 महीने की बहन की मौत के बाद पैदा हुआ है। इस घटना से व्यापक आक्रोश फैल गया है, प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है और कुछ क्षेत्रों में हिंसा की खबरें भी आई हैं। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और स्मोक बमों का इस्तेमाल किया है।

जेईई मेन के नतीजे घोषित, कबीर छिल्लर ने हासिल की पहला रैंक

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने बहुप्रतीक्षित जेईई मेन सेशन-2 2026 परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जो भी अभ्यर्थी अप्रैल 2026 सत्र की परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। परिणाम

देखने के लिए छात्रों को अपने लॉगिन विवरण की आवश्यता पड़ेगी। उम्मीदवार परिणाम पोर्टल पर अपना सही आवेदन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी जेईई मेन के रिजल्ट में इस बार भी कोटा का दबदबा देखने को मिला। कोटा के छात्र कबीर छिल्लर ने 300 में 300 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की। टॉप 10 में कोटा में पढ़ने वाले 4 छात्रों ने जगह बनाई, जिसमें पांचवां, छठा और आठवां स्थान भी शामिल है। देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2026 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी इन नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है।

भारत में कोरिया के राजकीय मेहमानों का भव्य स्वागत

नई दिल्ली। भारत दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का राजधानी दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान देश की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। राष्ट्रपति ली अपनी पत्नी किम ही क्यूंग के साथ तीन दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। इस दौरान पारंपरिक परिधानों में सजे बच्चों ने दोनों देशों के झंडे लहराकर मेहमानों का अभिवादन किया। अपनी यात्रा के दूसरे दिन, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, अपनी पत्नी प्रथम महिला किम ही क्यूंग के साथ, नई दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और प्रथम महिला ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। सोमवार को राष्ट्रपति ली और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने पौधारोपण भी किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह दौरा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।

अग्रिम जमानत की मांग लेकर पवन खेड़ा पहुंचे गुवाहाटी हाई कोर्ट

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने अब असम में दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) के लिए गौहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से

जुड़ा है, जिसमें पासपोर्ट को लेकर विवाद सामने आया है।

दरअसल, पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट हैं। इसी बयान के बाद उनके खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें चुनाव से जुड़े गलत बयान, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और शांति भंग करने जैसे आरोप शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर पवन खेड़ा असम की अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके मामले पर निष्पक्ष तरीके से विचार किया जाएगा और पहले के आदेश का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

केजरीवाल को झटका: जस्टिस शर्मा ही करेंगी सुनवाई

नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले में आज हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर अपना फैसला सुनाया। केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। इस दौरान केजरीवाल ने अपना जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने की मांग की। सुनवाई

को दौरान केजरीवाल ने कहा, मैडम अगर मेरा जवाब रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया तो यह न्याय के प्रति लापरवाही होगी। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा यदि किसी न्यायाधीश का फैसला ऊपरी अदालत द्वारा बदला जाता है तो किसी भी प्रतिवादी को यह कहने का हक नहीं है कि आमुख जज फैसला करने योग्य नहीं हैं। जज की क्षमताओं पर फैसला इसकी उच्च अदालत करती है ना की प्रतिवादी। अदालत में अखिल भारतीय देवता परिषद के कार्यक्रमों में न्यायमूर्ति के शामिल होने पर कहा कि वह महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई थीं, जिसमें उन्होंने जूनियर वकीलों और अन्य बार के सदस्यों को संबोधित किया था।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव

रैलियों की भीड़ से बदलते मूड के संकेत

बदलाव के मूड में दिख रहा पश्चिम बंगाल

बिमल राय

चुनावी मौसम में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग नेताओं को देखने-सुनने के साथ-साथ हेलिकॉप्टर देखने भी आते हैं। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में कश्मीर से आए बख्तरबंद वाहन लोगों में कौतुहल का विषय बने हुए हैं, जिसका इस्तेमाल आतंकी विरोधी अभियान में होता था। ये गाड़ियां बंगाल में संस्थागत रूप से जनादेश लूटने वालों को एक कड़ा संदेश दे रही हैं। बंगाल के पाले-पोसे गए दबंग इस बार शांत दिख रहे हैं। हालांकि वर्षों तक पशु तस्करी सहित अन्य कई मामलों में तिहाड़ प्रवास के बाद जमानत पर छूटे दबंग अणुव्रत मंडल की मानें, तो रॉयल बंगाल टाइगर इन्हें चबा जाएगा।

एक मार्च से ही पूरे राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की गश्त, छोटे-बड़े सौ से ज्यादा अफसरों के तबादलों सहित चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जिससे इस बार शांतिपूर्ण चुनाव की उम्मीद बंध रही है। आयोग के इस कदम के खिलाफ हाईकोर्ट में भी अपील की गई, जो खारिज कर दी गई। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के फैसले को नहीं पलटा। पिछले कई दशकों से यह साबित हो चुका है कि बंगाल में कोई भी चुनाव एक युद्ध जैसा होता है। चुनाव आयोग ने 23 अप्रैल को 152 सीटों पर होने वाले पहले चरण में ही सुरक्षा बलों की 2,407 कंपनियों की तैनाती के अलावा, एजेंटों को बूथों के बाहर टेंट लगाकर बैठाने, हर बूथ पर दो-दो कैमरे लगाने, दूसरे राज्यों के पुलिस पर्यवेक्षकों की बहाली, राज्य पुलिस को बूथ से 100 मीटर दूर रखने सहित कई नई व्यवस्थाएं करके 'वोट लुटेरों' के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा है।

जहां तक तृणमूल के एक खास वोट बैंक का सवाल है, बहुत सारे लोग समझ गए हैं कि एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से इतना बवाल नहीं किया गया होता, तो यह काम समय पर पूरा हो जाता और करीब 32 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं

होना पड़ता। तार्किक विसंगति वाले मामलों के निपटारे की प्रक्रिया में भी बाधा डाली गई। बीडीओ ऑफिस जलाए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने व उन पर जानलेवा हमले तक का दुस्साहस किया गया। लोगों को भड़काने वाले नेता और 'ऑन द स्पॉट' वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की मांग कर रहे कई लोगों को एनआईए ने पकड़ लिया है और कुछ फरार चल रहे हैं।एसआईआर में 91 हजार नाम कटने, और तार्किक विसंगति के मामलों का पूरा निपटारा नहीं होने के कारण करीब 32 लाख लोग इस बार वोटिंग नहीं कर पाएंगे। हालांकि 16 अप्रैल को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग से दो दिन पहले तक न्यायाधिकरणों द्वारा वैध ठहराए गए वोटरों को मताधिकार का हक दे दिया है। फिर भी अनुमानत: तार्किक विसंगति वाले 25-26 लाख लोग मताधिकार से वंचित रह ही जाएंगे। कम अंतर से जीत-हार वाली सीटों पर यह छंटनी भाजपा की मदद कर सकती है, क्योंकि जिनके नाम कटे हैं, उनमें से ज्यादातर तृणमूल समर्थक माने जाते हैं। ओवैसी व हुमायूं कबीर इसके लिए ममता को जिम्मेदार ठहराकर मुसलमानों का नया रहनुमा बनने का दम भर रहे हैं। पिछली बार 77 पर अटक जाने वाली भाजपा इस बार ममता पर व्यक्तिगत हमले करने से बच रही है। तृणमूल के 1500 रुपये के लक्ष्मी भंडार और बेरोजगारी भत्ते को भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में दोगुना कर दिया है। महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर और राज्य में उद्योग लगाने व कानून-व्यवस्था की हालत सुधारकर महिला सुरक्षा बढ़ाने यानी योगी मॉडल लागू करने की भी बात की गई है। कोलकाता के पास पानीहाटी से आरजी कर अस्पताल की पीड़िता की मां को टिकट देकर भाजपा ने महिला सुरक्षा के विमर्श को पूरे राज्य में जिंदा कर दिया है। रही बात कांगेस, वाम दलों, ओवैसी व हुमायूं कबीर के दलों की, तो ये दल कुछ सीटों पर भाजपा या तृणमूल की जीत-हार का कारण बन सकते हैं। वोटरों का संदेश जनसभाओं में आने वाले लोगों की शारीरिक भाषा से भी समझा जा सकता है। सिलीगुड़ी की एक बच्ची का वीडियो काफी वायरल हुआ है, जिसमें वह बच्ची पुलिस वाले से पूछ रही है कि 'पुलिस अंकल, मोदी जी कब तक आएंगे?' जबकि ममता और उनके भतीजे की जनसभाओं में पीछे की सीटें खाली जा रही हैं।

नक्सल क्षेत्र से उभर रही नई प्रतिभाएं, बस्तर के युवा शतरंज में बना रहे पहचान

अंडर-15 में मयंक और अंडर-11 में अयांश ने मारी बाजीं

बस्तर। जगदलपुर के निर्मल विद्यालय में आयोजित द चेस नेशन शतरंज चैम्पियनशिप 2026 का भव्य समापन हुआ, जहां प्रदेशभर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर बस्तर की बदलती तस्वीर को नई पहचान दी।

ओपन वर्ग में रायपुर के सालिक नवाज मणिहार ने पहला स्थान हासिल कर 11 हजार जीते।

बिलासपुर के रूपेश कुमार मिश्रा दूसरे और दुर्ग के यशद बंबेश्वर तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में अलंक्रुता मोहराना ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनकर बाजी मारी।

अंडर-15 वर्ग में कोंडागांव के मयंक श्रीवास्तव विजेता रहे, जबकि जगदलपुर के एजीकियल सर्विन एक्का दूसरे और अथर्व मेश्राम तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में आयुषी राठी सर्वश्रेष्ठ रहीं।

अंडर-11 वर्ग में जगदलपुर के अयांश दीक्षित ने पहला स्थान पाया। वेदांत शुक्ला दूसरे और सिद्धार्थ राव तीसरे स्थान पर रहे।

बालिका वर्ग में बृष्टि साहा ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बस्तर एसपी शलभ कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि रहे।

उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बस्तर अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यह आयोजन साबित करता है कि बस्तर की नई पीढ़ी अब बंदूक नहीं, बुद्धि की ताकत से पहचान बना रही है।

राखड़ बांध फूटने से सैकड़ों टन राख के नीचे दबा जेसीबी सहित ऑपरेटर, मौके पर मौत

■ 15 अप्रैल को राखड़ बांध की मरम्मत में लापरवाही के लिए अधीक्षण अभियंता को सस्पेंड किया गया था.

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के कोरबा स्थित हसदेव ताप विद्युत गृह के राखड़ बांध के फूटने से एक जेसीबी ऑपरेटर की मौत हो गई है। गांव झाबू स्थित राखड़ बांध में यह घटना अचानक हुई प्राकृतिक आपदा नहीं है।

एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है, जिसकी कीमत एक गरीब जेसीबी ऑपरेटर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। बीते 15 अप्रैल को बांध की मरम्मत में लापरवाही के आरोप में एक सब इंजीनियर विक्रांत तंवर को सस्पेंड किया गया था।

बावजूद इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया और मरम्मत में लगे एक जेसीबी ऑपरेटर की सैकड़ों टन राख के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई है। कुछ दिन पहले ही सक्ती में वेदांता पावर प्लांट में एक बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ। जिसमें मरने वालों की संख्या 24 पहुंच चुकी है। इसके ठीक बाद छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ है। इस बार यह हादसा राज्य के अपने पावर प्लांट के राखड़ बांध में हुआ है। रविवार की दोपहर 1340 मेगावाट क्षमता वाली एचपीएस इकाई के गांव झाबू में बांध का रखरखाव का काम चल रहा था।

शासकीय डीके कॉलेज के छात्रों ने तैयार किया हर्बल सैनेटाइजर

प्राचार्य ने की सराहना

बलौदाबाजार। शासकीय दाउ कल्याण सिंह महाविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के MSc yth semester के विद्यार्थियों ने एक प्रभावी herbal hand sanitizer तैयार किया है। इस सैनेटाइजर के निर्माण में प्राकृतिक तत्वों जैसे नीम, तुलसी, एलोवेरा एवं नींबू का उपयोग किया गया है, जो त्वचा के लिए सुरक्षित होने के साथ-साथ जीवाणुरोधी (antibacterial) गुण रखते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य बाजार में उपलब्ध रासायनिक सैनेटाइजर के विकल्प के रूप में एक सस्ता, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद विकसित करना है। प्रयोगशाला परीक्षणों में पाया गया कि यह सैनेटाइजर हाथों को साफ रखने में प्रभावी है तथा बार-बार उपयोग करने पर त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता। डॉ. ज्योति दीवान के दिशा निर्देश एवं विभागाध्यक्ष गणेश राम कुर्रे, डॉ. आकांक्षा एक्का व रुपेश देवांगन सहायक प्राध्यापक के कुशल मार्गदर्शन में छात्र-

छात्राओं ने हर्बल सैनिटाइजर का निर्माण किया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एके उपाध्याय ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को आगे भी ऐसे नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। एमएससी रसायन के सभी छात्र-छात्राओं मधु, शालिनी, शोभना, तेजस्वी, तेजस्विनी, पूजा, प्रीति वर्मा,निधि, नेहा, तरूण, धनेश्वर, शांति, सुमनलता, सोनम, जागृति,चंद्रानी,दीप्ति ,निकिता,देवेश, विनिका, तैय्यब सभी ने प्राचार्य को अपने हर्बल सैनिटाइजर की संपूर्ण जानकारी दी एवं विश्वास दिलाया कि भविष्य में भी सभी मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करने की कोशिश करेंगे।

छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व बना देशभर में मिसाल

'फायर-वॉटर' मॉडल बना ढाल

■ 143 बीट और 750 जल स्रोत से जंगल सुरक्षित, हाईटेक निगरानी से थमा संघर्ष, लगातार 3 साल जीरो हताहत

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ स्थित उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व (स्ङ्मक्र) ने अपने सभी 143 फॉरेस्ट बीट में समर्पित 'फायर वॉचर्स' और 'वॉटर वॉचर्स' की टीमों को तैनात कर वन्यजीव संरक्षण और सामुदायिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। ये प्रयास रिजर्व के कोर और बफर क्षेत्रों में स्थित लगभग 120 गांवों में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

गर्मी की चुनौतियां और रणनीति

गर्मी के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग और पानी के स्रोतों के सूखने के कारण अक्सर भालू, तेंदुए, लकड़बग्घे और हाथी जैसे जंगली जानवर मानवीय बस्तियों की ओर पलायन करते हैं। इससे संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। इस चुनौती से निपटने के लिए स्ङ्मक्र ने एक सक्रिय और एकीकृत रणनीति अपनाई है।

फायर वॉचर्स टीम

यह टीम नियमित पैदल गश्त करती है और जंगल की आग का पता लगाने व उसे रोकने के लिए थर्मल ड्रोन निगरानी का उपयोग करती है। इनकी सतर्कता के कारण आग लगाने के आरोप में 23 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिससे आग लगने की घटनाओं में भारी कमी आई है।

वॉटर वॉचर्स टीम

जंगली जानवरों के लिए जंगल के भीतर ही पानी सुनिश्चित करने व्यापक प्रयास किए गए हैं। आंतरिक वन क्षेत्रों में 750 से अधिक छोटे जल स्रोत, जिन्हें स्थानीय रूप से झिरिया कहा जाता है, बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 26 सौर-संचालित पंप स्थापित किए गए हैं। पानी के इस विस्तृत नेटवर्क के कारण वन्यजीव जंगल की सीमाओं के भीतर ही रहते हैं।

अवैध शिकार पर लगाम और तकनीक का उपयोग

ये उपाय अवैध शिकार को रोकने में भी सहायक हैं, क्योंकि शिकारी अक्सर गर्मियों में सीमित जल स्रोतों को निशाना बनाते हैं। स्ङ्मक्र की एंटी-पोचिंग टीम ने अंतर-राज्यीय शिकार नेटवर्कों पर कार्रवाई कर रिजर्व में सुरक्षा का माहौल बढ़ाया है। साथ ही सूखते जल स्रोतों और आग की आशंका वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए सैटेलाइट-आधारित मॉनिटरिंग का उपयोग किया जा रहा है।

उल्लेखनीय परिणाम

इन समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप, स्ङ्मक्र में पिछले तीन गर्मी के मौसमों के दौरान शून्य (जीरो) मानव या वन्यजीव हताहत दर्ज किए गए हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अवधि में स्थानीय समुदायों द्वारा महुआ, साल बीज, चिरौंजी और तेंदू पत्ता जैसे लघु वनोपज का संग्रहण किया जाता है। स्ङ्मक्र का पारिस्थितिक संरक्षण और सामुदायिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का एक आदर्श मॉडल है, जो दर्शाता है कि कैसे लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से संवेदनशील वन क्षेत्रों में संघर्ष को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।

देर रात निर्माधणीन मकान की दीवार गिरी, दंपति और मासूम घायल

कोरबा। शहर के कपाटमुडा रोड स्थित देर रात एक परिवार पर उस वक्त आफत आ गई, जब मौसम का रुख बदलने से पड़ोस की निर्माणधीन बिल्डिंग की दीवार उनके घर पर गिर गई। हादसे में सो रहे पति-पत्नी और बच्चा मलबे में दब गए। सभी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घर में रखे दोपहिया और सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

बीती रात शहर में मौसम का मिजाज बदला, भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत तो मिली, लेकिन एक परिवार पर आफत टूट पड़ी। कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम नगर के कपाटमुडा रोड की पूरी घटना है। निर्माणधीन तीन मंजिला बिल्डिंग अचानक भरभराकर पड़ोस के

अजय धनवार के घर पर जा गिरी। जानकारी के मुताबिक, संतोष वर्मा द्वारा बनवाए जा रहे मकान की दीवार गिरने से अजय धनवार, उनकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा घर के अंदर सो रहे थे। हादसे के दौरान ईंटों के मलबे में दब गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकल और अस्पताल के लिए भेजा। घर के अंदर रखा दोपहिया स्कूटर, बर्तन, बिस्तर और अन्य सामान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान के भीतर अभी भी ईंटों का मलबा बिखरा पड़ा है।

जातिसूचक टिप्पणी करने पर नेता प्रतिपक्ष का हंगामा

धमतरी। आमदी नगर पंचायत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष,उपाध्यक्ष और बीजेपी पार्षद पर जातिसूचक टिप्पणी के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार का विरोध करते हुए मोर्चा खोला और नगर पंचायत का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए परिसर के सामने धरना दिया। कांग्रेस के विरोध को देखते हुए नगर पंचायत के सामने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आमदी नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष ऋषभ ठाकुर ने आरोप लगाते हुए बताया कि 13 अप्रैल को आयोजित सामान्य सभा की बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके पार्षद दोपहर 1 बजे तक

उपस्थित नहीं हुए थे। जब उन्होंने देरी को लेकर सवाल किया, तो उन्हें केबिन में बुलाकर उनके और उनके पिता के खिलाफ जाति सूचक गालियां दी। साथ ही यह भी कहा गया कि वे सामान्य सभा में किसी भी प्रकार का सवाल-जवाब नहीं करेंगे। आपको बता दें कि प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि मामले में नियमानुसार जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प 5 घायल 2 की हालत गंभीर

कोरिया। जिले के चरचा थाना क्षेत्र में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब बाजार पारा इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर हिंसा भड़क उठी। रात करीब 10 बजे हुई इस घटना में धारदार हथियारों और ईंट-पत्थर से हमला किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, चरचा कॉलरी के बाजार पारा में हुए विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें कुल पांच लोग घायल हो गए। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत रीजनल अस्पताल चरचा और जिला अस्पताल बैकुंठपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुरानी रंजिश और आपसी विवाद के चलते अचानक स्थिति बेकाबू हो गई और देखते ही देखते कई लोग हमले की चपेट में आ गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और लोग सहमे हुए हैं। इस मामले में चरचा थाना प्रभारी आनंद सोनी ने बताया कि यह घटना पुरानी रंजिश से जुड़ी हुई है। दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। रविवार रात दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने आ गए, जिसके बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सूचना मिलते ही चरचा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल तलाश जारी है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

एएसआई ने बीजेपी कार्यकर्ता को जड़े 20 थप्पड़,कान सुन्न पड़ा

बिलासपुर। बिलासपुर में अपने केस की जांनकारी लेने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता को,स्ढ्ढ ने कनपटी पर 20 थप्पड़ जड़ दिए। जिससे उसका कान सुन्न पड़ गया। एएसआई दिनेश तिवारी ने पीड़ित से कहा कि, बड़ा नेता है, तेरी सब नेतागिरी निकाल दूंगा, तुझे जेल भिजवा दूंगा। अब इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला रनतपुर थाने का है। दरअसल, रतनपुर के बनियापारा निवासी विनोद जायसवाल 12 अप्रैल को अपने पुराने केस की जानकारी लेने थाने पहुंचा था। दोपहर करीब 2.30 बजे विनोद की मुलाकात एएसआई दिनेश तिवारी से हुई। विनोद ने अपने केस की जानकारी मांगी और जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आग्रह किया। इसी बात पर एएसआई नाराज हो गया और मारपीट शुरू कर दी। विनोद जायसवाल ने बताया कि, एएसआई ने गाली-गलौज करते हुए 15-20 थप्पड़ जड़ दिए। घटना के समय थाने में बाकी स्टाफ भी मौजूद थे। मारपीट के दौरान एएसआई ने धमकी भी दी कि तू कितना बड़ा नेता है, तेरी नेतागिरी निकाल दूंगा, तुझे जेल भिजवा दूंगा।

बस्तर में 1300 से ज्यादा फड़ों में होगी तेंदूपत्ता खरीदी

जगदलपुर। बस्तर के जंगलों से निकलने वाला हरा सोना अब एक बार फिर हजारों परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लेकर आने वाला है। तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार रिकॉर्ड खरीदी की उम्मीद जताई जा रही है। बस्तर सर्किल के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर जिले में इस वर्ष 2 लाख 70 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा संग्रहण की उम्मीद बीजापुर जिले से की जा रही है, जहां जंगलों में तेंदूपत्ता की अच्छी पैदावार के संकेत मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार मौसम अनुकूल है, ऐसे में उत्पादन बेहतर रहने और पिछले वर्षों के मुकाबले ज्यादा संग्रहण होने की संभावना है। यही वजह है कि वन विभाग ने पहले से ही खरीदी व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। पूरे बस्तर सर्किल में 75 समितियों के माध्यम से 119 लॉट बनाए गए हैं, जहां संग्रहण कार्य संचालित होगा। वहीं तेंदूपत्ता को समय पर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए 43 परिवहन समूह भी गठित किए गए हैं।

सरकारी गेस्ट हाउस में अफसरों की शराब पार्टी

कोरबा। कोरबा में सरकारी गेस्ट हाउस में डीएसपीएम प्लांट (डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन) के चीफ केमिस्ट गोवर्धन सिदार समेत 5 अफसर शराब पीते पकड़ाए हैं। उनकी शराब पार्टी की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। मौके से बीयर और शराब की बोतल मिली है। इसी गेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं की मीटिंग थी, तब कार्यकर्ताओं को कमरे में सिगरेट का धुआं भरा दिखा। उन्होंने इसकी सूचना मंत्री लखनलाल देवांगन को दी। मंत्री ने एमपी को कॉल कर अधिकारियों पर कार्रवाई करने कहा है। एमडी ने जांच के बाद एक्शन लेने की बात कही है। मामला सीएसईबी पुलिस चौकी क्षेत्र का है। दरअसल, शनिवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक कोरबा दौरे पर थे, उनसे मिलने के लिए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, महापौर संजू देवी राजपूत और जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल मोदी वीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं को गेस्ट हाउस के कमरे से तेज आवाज और सिगरेट की गंध आ रही थी।

दो मामलों में अज्ञात चोर 2.55 लाख ले भागे,मामला दर्ज

रायगढ़। जिला में बाइक की डिक्की को खोलकर अज्ञात चोरों ने ढाई लाख से अधिक रुपए की चोरी कर ली। दो अलग-अलग मामलों में बैंक से रुपए निकालकर ग्रामीण रास्ते में कुछ देर के लिए रूके थे। तभी अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक पहली घटना में ग्राम गेरूपानी उरांवपारा का रहने वाला शिव प्रसाद भगत 37 साल शुक्रवार की सुबह अपने प्लेटिना वाहन से स्टेट बैंक लैलूंगा रुपए निकालने गया था। स्टेट बैंक लैलूंगा से 2 लाख 15 हजार रुपये निकाला और प्लास्टिक में उसे डालकर पासबुक, चेकबुक, राशन कार्ड को मोटर सायकल की डिक्की में रखकर घर के लिए निकला। तभी रास्ते में टीव्हीएस शो रूम लैलूंगा से घरघोड़ा रोड में गैरेज के पास अपनी बाइक को बनवाने के लिए रूका था। बाइक में सुधार हो जाने के बाद उसका रुपये देने के लिए गैरेज अंदर गया और वापस आकर उसने अपनी बाइक की डिक्की को देखा तो वह खुला था और उसमें रखे 2 लाख 15 हजार रुपए, पासबुक, चेकबुक, राशन कार्ड नहीं था।

कल्याण और राजधानी सट्टा एप से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग-भिलाई। दुर्ग में वैशालीनगर पुलिस ने कल्याण और राजधानी नाम के सट्टा गेम में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस पर अंकों में पैसे लगाकर अवैध सट्टा चलाने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल सट्टा संचालन में किया जा रहा था। जांच के दौरान पुलिस को इस सट्टा कारोबार में शामिल बाकी लोगों की जानकारी मिली। इसी आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी की पहचान संतोष शर्मा उर्फ संतन (40) के रूप में की। वह हाउसिंग बोर्ड, कैलाशनगर, थाना जामुल क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने उसे 19 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया। 17 अप्रैल को सूचना मिली थी कि, जवाहर नगर पुलिया के पास कुछ लोग मिलकर सट्टा खेल रहे और दूसरों को भी खिला रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान एक आरोपी को मौके से पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पास से एक सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप-6 मोबाइल फोन जब्त।

लाल आतंक का ऐसे हुआ अंत

संजीव शर्मा

भारत के जिन क्षेत्रों में कभी बंदूक की आवाज ही कानून हुआ करती थी, आज वहां विकास की गूंज सुनाई दे रही है। दशकों तक देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाले नक्सलवाद का अब अंत हो चुका है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुनियोजित रणनीति, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और जमीनी स्तर पर समन्वित प्रयासों का परिणाम है। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से जमींदारों के विरोध में हुई थी। धीरे-धीरे यह आंदोलन देश के कई राज्यों में फैल गया और 2000 के दशक तक इसने भारत के 17 प्रतिशत भूभाग को अपनी चपेट में ले लिया जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा। लगभग 12 करोड़ लोग

माओवादी हिंसा की चपेट में आ गए। 2004 में विभिन्न नक्सली गुटों के एकजुट होकर सीपीआई (माओवादी) बनने के बाद यह आंदोलन और संगठित हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 2010 के आसपास देश के 96 जिले माओवादी हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित थे और 126 जिलों को नक्सल प्रभावित माना जाता था। मगर आज यह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यह सिर्फ भौगोलिक सिकुड़न नहीं है, बल्कि एक विचारधारा और हिंसक तंत्र के पतन की कहानी है। नक्सलवाद के अंत की असली शुरुआत 2014 में केंद्र में नई सरकार बनने के बाद देखने को मिली, जब पहली बार केंद्र सरकार ने इसके खात्मे के लिए एक एकीकृत और स्पष्ट नीति अपनाई। 2015 में वामपंथी उग्रवाद से निपटने की राष्ट्रीय नीति लाई गई जिसमें सुरक्षा, विकास और पुनर्वास तीनों को एक साथ जोड़ा गया। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता थी एक टीम, एक लक्ष्य का दृष्टिकोण, केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और खुफिया जानकारी का रीयल-टाइम साझा करना। पहले जहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई प्रतिक्रियात्मक होती थी, इस नीति के बाद सरकार ने पहल अपने हाथ में ले ली। इस नीति के तहत सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए दोहरी रणनीति अपनाई। हथियार छोड़ समर्पण करने और मुख्यधारा में शामिल होने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास एवं सम्मान और हिंसा जारी रखने वालों के लिए सख्त कार्रवाई की नीति सरकार ने अपनाई। यानी गोली का जवाब गोली से और बोली का जवाब बोली से। समर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए आर्थिक पैकेज, रोजगार, आवास और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं दी गईं। इसका असर यह हुआ कि बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौटने लगे। वहीं दूसरी ओर, सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी गई कि वे हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस स्पष्ट नीति ने भ्रम खत्म किया और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया।

पिछले एक दशक में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के परिणाम बेहद प्रभावशाली रहे और यह नासूर अब मिट चुका है। इस नीति की बदौलत हाल के वर्षों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों से कहीं ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया। नक्सली संगठनों की रीढ़ उसके शीर्ष नेतृत्व में होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों के व्यापक अभियान से यह बिखर गया। इन अभियानों में शीर्ष नेताओं का सफाया या गिरफ्तारी, सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव से आत्मसर्पण में आई तेजी से संगठन छोटे-छोटे समूहों में बंट कर रह गया। जो नेता कभी क्रांतिकारी जोन बनाने का सपना देखते थे, वे जंगलों में छिपकर अस्तित्व बचाने की कोशिश करने लगे। नक्सलवाद के अंत की असली कुंजी सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास रहा। इन क्षेत्रों में 14 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का जाल बिछाया गया, हजारों मोबाइल टावर लगाए, बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचाई गई और स्कूल, आईटीआई एवं स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। जिन क्षेत्रों में कभी सरकारी तंत्र का नामोनिशान नहीं था, वहां आज बैंक, इंटरनेट और पक्के घर उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ की नियाद नेल्ला नार जैसी योजनाओं ने गांवों में सीधे विकास पहुंचाया, जिससे लोगों का भरोसा सरकार पर बढ़ा और नक्सलियों का प्रभाव घटा। नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए अपनाई गई नई नीति में सुरक्षा अभियानों में भी बड़ा बदलाव आया।

तकनीक के माध्यम से ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी को बढ़ाया गया जिससे सुरक्षा बलों को नक्सलियों की सटीक जानकारी मिलने लगी। साथ ही उन्हें आधुनिक हथियार और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए गए। यही नहीं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल को बढ़ाए जाने से नक्सलियों के बारे में रियल टाइम जानकारी मिलने लगी जिससे ऑपरेशन की सफलता बढ़ गई।

संक्षिप्त समाचार

आम सभी की बैठक में नई योजनाओं पर हुई चर्चा, शेड क्रमांक 1 का हुआ उद्घाटन, 51 गौमाताओं का प्रवेश

रायपुर। अग्र सेवा सोसायटी की उप-समिति, अग्र सेवा गौशाला, (निर्माणाधीन) ग्राम तर्रा में आयोजित आम सभा एजेंडा अनुसार सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के पदाधिकारियों एवं गौशाला निर्माण में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले सम्माननीय दानदाताओं के करकमलों से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। बैठक में गौशाला के समग्र विकास, अग्र सेवा सोसायटी द्वारा संचालित गोकुल नगर, गोठान के संचालन, अग्र सेवा की जनमानस के लिए अन्य सेवाओ में विस्तार और नई योजनाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान निर्माणाधीन गौशाला परिसर में अधिकतम सोलर सिस्टम के उपयोग और सर्वसमाज की सेवा के अंतर्गत डायलिसिस पीड़ित मरीजों की सेवा के लिए सेवा केंद्र प्रारंभ करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।

करेंसी टावर में लापरवाही उजागर, 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव ऋचा शर्मा

रायपुर। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित करेंसी टावर में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब छत्तीसगढ़ शासन की अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) ऋचा शर्मा लिफ्ट में फंस गईं। जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह करीब 6ः30 बजे की है, जब (एसीएस) ऋचा शर्मा लगभग 10 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसी रहीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लिफ्ट के भीतर न पर्याप्त रोशनी थी और न ही हवा की उचित व्यवस्था, जिससे अधिकारी को घबराहट होने लगी। स्थिति बिगड़ने पर वे परेशान होकर रोने लगीं और कुछ समय तक काफी तनाव में रहीं। बताया गया कि लिफ्ट में इमरजेंसी अलार्म सिस्टम और हेल्पलाइन नंबर जैसी आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं भी मौजूद नहीं थीं, जिसके चलते मदद पहुंचने में देरी हुई। सूत्रों के अनुसार, (एसीएस) ने किसी तरह अपने फोन से प्रशासनिक अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने उर्जा सचिव डॉ. रोहित यादव को भी कॉल कर कॉम्प्लेक्स की व्यवस्थाओं, पावर बैकअप और सोलर पावर सिस्टम को लेकर जानकारी ली और सवाल उठाए। घटना की सूचना मिलते ही तेलीबांधा पुलिस की टीम भी तत्काल मौके पर पहुंची। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा खोला गया। बाहर आने के बाद उनकी हालत काफी असहज बताई गई और उन्हें कुछ समय तक संभलने में दिक्कत हुई। लोगों का कहना है कि करेंसी टावर में लिफ्ट फंसने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार लोग लिफ्ट में फंस चुके हैं और कुछ मामलों में लोग बेहोशी जैसी स्थिति में भी पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टावर की सातवीं मंजिल पर ख्रुष्टस् त्नङ्करूसंचालित है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग और प्रशासनिक अधिकारी आते हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चंद्राकर का कांग्रेस-टीएमसी पर गंभीर आरोप

रायपुर। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, परिसीमन और नक्सलवाद जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस और टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष ने षड्यंत्रपूर्वक लोकसभा में प्रभावित किया, जिससे देशभर की मातृशक्ति में आक्रोश है और इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी अभियान चलाएगी। अजय चंद्राकर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष ने षड्यंत्रपूर्वक लोकसभा में प्रभावित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और टीएमसी ने मिलकर इस बिल को गिराने का काम किया, जिससे देशभर की मातृशक्ति में आक्रोश है। चंद्राकर ने कहा कि इस मुद्दे को अब ग्रासरूट स्तर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी अभियान चलाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनसंख्या संतुलन के लिए परिसीमन आवश्यक था, लेकिन इस पर भी राजनीति की जा रही है। चंद्राकर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित न होने के मुद्दे को लेकर बीजेपी व्यापक जनजागरण अभियान चलाएगी ताकि यह संदेश जनता तक पहुंच सके। नक्सलवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 देश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बड़ी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ और देश में नक्सलवाद की जड़ें कांग्रेस शासनकाल की नीतियों और शोषण आधारित विकास मॉडल से जुड़ी हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ा और कम्युनिस्ट संगठन बने।

ट्रेफिक सिंग्नल में प्रतीक्षा करने वालों को अब तेज धूप व बारिश में नहीं होगी परेशानी

उद्योग मंत्री देवांगन व महापौर राजपूत ने सीएसईबी चौक में 32 लाख 30 हजारसे बनने वाले 2 प्रतीक्षा शेड निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन

रायपुर। शहर के चौक-चौराहों में लगे ट्रेफिक सिंग्नल के लाल होने के कारण नागरिको वाहन चालकों के रूकने के समय तेज धूप व बारिश के पानी से अब परेशानी नही होगी क्योंकि निगम शहर के ट्रेफिक सिग्नल वाले प्रमुख चौक-चौराहों में प्रतीक्षा शेड का निर्माण करा रहा है। रविवार को प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने सीएसईबी चौक में 32 लाख 30 हजार रूपये की लागत से बनने जा रहे 02 प्रतीक्षा शेड के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।

कोरबा शहर के विभिन्न चौक. चौराहों में आवागमन व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के मद्देनजर ट्रेफिक सिग्नल स्थापित किये गये हैंए इन चौक-चौराहों से गुजरने वाले नागरिकों, वाहन चालकों को ट्रेफिक लाल होने के समय रूक कर प्रतीक्षा करनी होती है जिससे विशेष रूप से तेज धूप व बारिश के दौरान उन्हें परेशानी होती है। नागरिकों,

वाहन चालकों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाने हेतु नगर पालिक निगम केारबा द्वारा शहर के विभिन्न चौक-चौराहों में सड़क के ऊपर प्रतीक्षा शेड बनाये जाने की योजना बनाई गई है। प्रारंभ में सीएसईबी चौक में 02 नग प्रतीक्षा शेड बनाये जायेंगे जिनका भूमिपूजन रविवार को उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत के करकमलों से सम्पन्न हुआ तथा प्रतीक्षा शेड का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया।

आमजन को गर्मी, बरसात में नही होगी परेशानी

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि चौक-चौराहों पर सड़क के ऊपर प्रतीक्षा शेड बन जाने से गर्मी की तेज धूप व बारिश के पानी से अब आमनागरिकों वाहन चालकों को परेशानी नही होगी महापौर श्रीमती राजपूत का यह कार्य सराहनीय है जो उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। कोरबा शहर के सड़कों के डामरीकरण की चर्चा करते हुये उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि शहर की सभी सड़कों के डामरीकरण नवीनीकरण हेतु शासन द्वारा राशि स्वीकृत किये जाने के बाद निविदा आदि की कार्यवाही पूरी कर ली गई है 02 प्रमुख सड़कों के डामरीकरण का भूमिपूजन भी किया जा चुका है किन्तु ईरान इजरायल युद्ध के परिणाम स्वरूप डामर मिलने में अत्यंत कठिनाई हो रही है ठेकेदारों को डामर नहीं मिल पा रहा है इसके कारण डामरीकरण कार्य में देरी हो रही है, उन्होने कहा कि जैसे ही डामर की उपलब्धता बनेगी तेजी के साथ शहर की सड़कों का कायाकल्प कर दिया जायेगा। उन्होने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव के आशीर्वाद से कोरबा में विकास कार्यो हेतु धनराशि की कोई कमी नहीं हो रही तथा कोरबा का तेजी से विकास हो रहा है।

उद्योग मंत्री की प्रेरणा से बन रहे प्रतीक्षा शेड

महापौर श्रीमती राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की प्रेरणा से मेरे मन में विचार आया कि सिग्नल के दौरान चौक-चौराहों में रूकने के दौरान तेज धूप व बारिश से आमलोगों को होने वाली परेशानी से कैसे छुटकारा दिलाया जाय तब चौक-चौराहों में प्रतीक्षा शेड निर्माण की योजना बनी जिसके प्रथम चरण में सीएसईबी चौक में 32 लाख 30 हजार रूपये की लागत से 02 प्रतीक्षा शेड बनेंगे इसके बाद दूसरे प्रमुख चौक.चौराहों पर भी शेडों का निर्माण होगा उन्होने बताया कि सीएसईबी चौक में आमनागरिकों की सुविधा हेतु सर्वसुविधायुक्त शौचालय भी बनाया जा रहा है वहीं चौक में स्थित पुराने जर्जर प्रतीक्षालय के स्थान पर सर्वसुविधायुक्त आधुनिक व वातानुकूलित प्रतीक्षालय का निर्माण भी कराया जायेगा। उद्योग मंत्री देवांगन एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत द्वारा सुभाष ब्लाक जैतखंभ के पास सतनामी समाज के लिये 15 लाख रूपये की लागत से बनने जा रहे सामुदायिक भवन एवं हेलीपेड के पास किन्नर समाज के लिये 10 लाख रूपये से बनने जा रहे हैं।

आम चुनाव और उपचुनाव 2026 अवैध सोशल मीडिया सामग्री पर ईसीआई की कार्रवाइ

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने दोहराया है कि सभी हितधारक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, आईटी नियम, 2021 और आदर्श आचार संहिता सहित मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिम्मेदार और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करेंगे। आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी भ्रामक या अवैध एआई-जनित या हेरफेर की गई सामग्री पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संज्ञान में लाए जाने के 3 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अभियान प्रतिनिधियों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रचार के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी सिंथेटिक रूप से निर्मित या एआई-परिवर्तित सामग्री को स्पष्ट रूप से एआई-जनित, डिजिटल रूप से संवर्धित या सिंथेटिक सामग्री के रूप में लेबल किया जाए, साथ ही पारदर्शिता और मतदाता विश्वास बनाए रखने के लिए मूल इकाई का खुलासा भी किया जाए।

असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के चल रहे चुनावों में, ऐसी सोशल मीडिया सामग्री जैसे कि पोस्ट जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हैं, कानून और व्यवस्था को बाधित करते हैं या जिनमें बाधित करने की क्षमता है, और मतदान प्रक्रिया या मशीनरी के खिलाफ झूठी कहानियों की निगरानी की जा रही है और आईटी अधिनियम के तहत अधिसूचित संबंधित राज्य आईटी नोडल अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है। तदनुसार 15 मार्च 2026 को चुनावों की घोषणा के बाद से चल रहे चुनावों में सामग्री को हटाने, एफआईआर , स्पष्टीकरण और खंडन सहित 11 हजार से अधिक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट/यूआरएल की पहचान की गई है और उन पर कार्रवाई की गई है।

आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत प्रावधानों को भी दोहराया, जो मतदान की समाप्ति से पहले 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान मतदान क्षेत्रों में किसी भी चुनावी मामले के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करते हैं। टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और सोशल मीडिया सहित मीडिया प्लेटफॉर्मों को इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, नागरिक/राजनीतिक दल/उम्मीदवार ईसीआई-नेट पर सी-विजिल मॉड्यूल का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं।

भाठागांव में पानी टंकी की पाइपलाइन फूटी

रायपुर। रायपुर के भाठागांव इलाके में पानी टंकी की पाइपलाइन फटने से घंटों तक पानी फव्वारे की तरह बहता रहा। मामला सुबह 8 बजे का है, हैरानी की बात यह है कि यह घटना ऐसे समय हुई जब शहर के कई हिस्सों में पानी की किल्लत चरम पर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पाइपलाइन फूटने के बाद काफी देर तक पानी लगातार बहता रहा, लेकिन समय पर सुधार के लिए कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। इससे बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो गया। शहर के कई इलाकों में लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं और टैंकरों पर निर्भर हैं। वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं जल प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रही हैं। घटना के बाद लोगों में नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जहां पानी की एक-एक बूंद की जरूरत है, वहां इस तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में पानी की समस्या और गंभीर होती जा रही है। ऐसे में पाइपलाइन फूटने जैसी घटनाएं हालात को और बिगाड़ सकती हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पाइपलाइन की मरम्मत की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

कुछ दिन पहले 100 एकड़ के जमीन की फाइल हुई थी गायब

रायपुर ननि से एक और फाइल गायब

रायपुर। रायपुर में नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित गार्डन से जुड़ी अहम फाइल गायब होने का मामला सामने आया है। पहले से ही फूड पार्क की शर्तों के उल्लंघन को लेकर विवादों में रहे इस गार्डन को लेकर अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कुछ दिन पहले जोन-10 से जुड़ी फाइल गायब होने की घटना सामने आई थी। अब मुख्यालय स्तर पर फाइल लापता होने से यह मामला और गंभीर हो गया है। अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं।

व्यावसायिक उपयोग पर उठे सवाल

जानकारी के अनुसार, गार्डन के रखरखाव और सुविधाओं के लिए निजी एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई थी। इसके तहत सीमित हिस्से में दुकानों और फूड स्टॉल की अनुमति दी गई थी, लेकिन आरोप है कि निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग किया गया।

नियमों का पालन नहीं होने की शिकायत

निगम के नियमों के मुताबिक, उद्यान के कुल क्षेत्रफल के केवल 5 प्रतिशत हिस्से में ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। साथ ही सुरक्षा, साफ-सफाई और सीसीटीवी व्यवस्था सुनिश्चित करना भी एजेंसी की जिम्मेदारी होती है।

इसके बावजूद मौके पर इन व्यवस्थाओं में कमी और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें

जांच के बाद होगी कार्रवाई-महापौर

महापौर मीनल चौबे ने दिए जांच के आदेश महापौर मीनल चौबे का कहना है कि गार्डन से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सामने आती रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि गड़बड़ियों को छिपाने के लिए दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई हो सकती है। यह गार्डन पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है। रखरखाव, दुकानों की संख्या और नियमों के उल्लंघन को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। फिलहाल, फाइल गायब होने के इस नए मामले ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। रायपुर में नगर निगम के जोन 10 अमलीडीह ऑफिस से करीब 100 एकड़ जमीन से जुड़ी अहम फाइल गायब हो गई है। इस गड़बड़ी के पीछे बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है।

महिला आरक्षण पर भारतहय की कथनी और करनी में फर्क : दुर्गा झा

रायपुर। आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर महिला आरक्षण को लेकर तीखा हमला बोला है। प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा झा ने आरोप लगाया कि सरकार ने 2023 में महिला आरक्षण कानून पारित कर 33 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का दावा तो किया, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की मंशा साफ होती तो वर्तमान 543 लोकसभा सीटों में ही लगभग 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती थीं। उनका आरोप है कि ऐसा करने से कई मौजूदा नेताओं की राजनीतिक स्थिति प्रभावित होती,

इसलिए सीटों की संख्या बढ़ाने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिससे सभी पक्षों को संतुष्ट रखा जा सके। प्रदेश अध्यक्ष (महिला विंग) मिथलेश बघेल ने पंचायत स्तर का उदाहरण देते हुए कहा कि कई जगहों पर महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिजन निर्णय लेते हैं, जिसे आम बोलचाल में प्रधान पति मॉडल कहा जाता है। उनके अनुसार, यही व्यवस्था बड़े स्तर पर भी लागू होने का खतरा है, जहां महिलाओं के नाम पर प्रतिनिधित्व होगा लेकिन वास्तविक नियंत्रण पुरुषों के हाथ में रहेगा।

मिथलेश बघेल ने महिला सुरक्षा के मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि जमीनी स्तर पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी नहीं आई है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि अलग-अलग राज्यों में जनसंख्या और सीटों के आधार पर होने वाले बदलाव से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ सकता है। जनता को भावनात्मक मुद्दों में उलझाने के बजाय ठोस सुधारों की जरूरत है और महिला सशक्तिकरण को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।

विद्यार्थियों ने पक्षियों के लिए बनाए घोंसले, संवेदनशील शिक्षा का दिया संदेश

रायपुर। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता का समावेश भी आवश्यक है। इसी सोच को साकार करते हुए जिला प्रशासन के मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन में सारागांव हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने एक प्रेरणादायक पहल की है।

विद्यालय में आयोजित समर कैम्प के दौरान कक्षा 12वीं की छात्राओं—छाया, साक्षी और टीना ने मिलकर पक्षियों के लिए सुरक्षित एवं आकर्षक घोंसलों का निर्माण किया। इन घोंसलों को रचनात्मक ढंग से तैयार कर विद्यालय परिसर के पेड़ों पर स्थापित किया गया, जिससे भीषण गर्मी में पक्षियों को आश्रय और सुरक्षा मिल सके। विद्यार्थियों की इस पहल ने पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जीवों के प्रति करुणा और जिम्मेदारी का संदेश दिया है। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों में सामाजिक सरोकार, सहयोग और प्रकृति के प्रति जुड़ाव की भावना को भी बढ़ावा मिला है।

बरडीह जलाशय की नहर लाईनिंग कार्य के लिए 2.43 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा रायपुर जिले के विकासखण्ड-धरसींवा की बरडीह जलाशय के नहर लाईनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए 02 करोड़ 43 लाख 98 हजार रुपये की राशि स्वीकृत किये गये हैं। योजना के प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण होने पर रूपांकित सिंचाई क्षमता 101 हेक्टेयर के विरूद्ध 41 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। योजना के कार्य को पूर्ण कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी गोदीवरी कछार, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

पीएम आवास योजना ने बदली मन्नू-बिमला राठौर की जिंदगी

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीणों को मिल रहा सुरक्षित आवास

रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के संवेदनशील नेतृत्व और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अब गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना तेजी से साकार हो रहा है। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण जनपद पंचायत गौरेला के ग्राम पंचायत गोरखपुर में देखने को मिला, जहां श्री मन्नू राठौर और उनकी पत्नी श्रीमती बिमला राठौर ने योजना का लाभ लेकर अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। कभी कच्चे और जर्जर मकान में जीवन यापन करने वाला यह परिवार हर मौसम में कठिनाइयों का सामना करता था। बरसात में टपकती छत, गर्मी और सर्दी में असुरक्षित वातावरण

ने उनके जीवन को बेहद चुनौतीपूर्ण बना रखा था। सीमित आय के कारण पक्का घर बनाना उनके लिए एक दूर का सपना था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृति मिली। यह आर्थिक सहायता उनके जीवन में नई उम्मीद बनकर आई। योजना से प्राप्त राशि और अपनी मेहनत के बल पर मन्नू राठौर ने धीरे-धीरे अपने सपनों का पक्का घर तैयार कर लिया।

आज उनका परिवार एक सुरक्षित, स्वच्छ और मजबूत मकान में निवास कर रहा है। बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिला है, वहीं पूरे परिवार के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है। श्रीमती बिमला राठौर बताती हैं कि अब उन्हें बारिश या तूफान की कोई चिंता नहीं रहती और वे अपने घर में गर्व और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास निरंतर जारी है। साय सरकार की प्रतिबद्धता के चलते ही आज हजारों जरूरतमंद परिवारों को न केवल पक्का आवास मिल रहा है, बल्कि उनके जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और सम्मान भी सुनिश्चित हो रहा है।

रेलवे समपार फाटक भैसबोङ गेट स्थायी रूप से बंद

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल अंतर्गत मुंबई-हावडा मुख्य मार्ग पर दगौरी-बिल्हा स्टेशनों के मध्य किमी-736/3-5 में समपार फाटक संख्या-374 (भैसबोड गेट) स्थित है. जहाँ समपार फाटक संख्या-374 के नजदीक आर यू. बी. का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं आमजनों के आवागमन के लिए 28.03.2026 से चालू कर दिया गया है साथ हीं, समपार फाटक सं.-374 को स्थायी रूप से बंद करने की पीसीई स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। अतः किमी.-736/3-5 में स्थित समपार फाटक संख्या-374 (भैसबोङगेट) को स्थायी रूप से बंद किया गया हैं।

चार राज्यों के चुनाव में भाजपा की जीत तय?

सनत जैन

केंद्र सरकार और भाजपा ने मिलकर विपक्ष को अपने जाल में बुरी तरह से फंसा लिया है। जिस तरह की स्थिति परिसीमन बिल के संसद में गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव में महिलाओं के आरक्षण का जो मुद्दा तैयार किया है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के ऊपर जिस तरह का हमला चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है, भाजपा चार राज्यों के विधानसभा चुनाव को स्पष्ट बहुमत के साथ जीतने का जो नॉरेटिव बनाना चाहती थी। वह भाजपा ने बना लिया है। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यों की विधानसभा में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। असम, केरल और पांडिचेरी में पहले ही 9 अप्रैल को मतदान हो चुका है। भाजपा ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया इसमें परिसीमन बिल को संशोधन के लिए लाया गया। सरकार ने परिसीमन बिल के स्थान पर इसे महिला आरक्षण बिल के नाम पर प्रचारित किया है। उसमें उन्हें पता था, विपक्ष परिसीमन के इस बिल को स्वीकार नहीं करेगा, लोकसभा में यह बिल पास नहीं होगा। उसके बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में महिला आरक्षण के मुद्दे पर महिला मतदाता के समर्थन से चुनाव जीतने का सुनयोजित रूप से नेरेटिव बनाया जाएगा। उसी रणनीति के तहत भाजपा काम कर रही है। इसके पहले तीन तलाक के मुद्दे पर जो नेरेटिव भाजपा ने महिला मतदाताओं के नाम से तैयार किया था। उसके आधार पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में भाजपा को बड़ी संख्यि में मुस्लिम महिलाओं के वोट मिले। भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा भाजपा के पक्ष में मतदान करने का दावा किया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार इत्यादि के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसी तरह से पहले नॉरेटिव तैयार किया। जमीनी स्तर पर भाजपा का भारी विरोध होने के बाद भी इन सभी राज्यों में भाजपा को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई। भाजपा ने हर राज्य में नेरेटिव से जोड़कर जीत हासिल की। इसमें चुनाव आयोग की भी बड़ी भूमिका थी। इस बार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को लेकर पिछले 1 वर्ष से भाजपा लगातार प्रयासरत थी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के कुछ माह पहले एसआईआर का खेल शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में एसआईआर में वोट काटे और जोड़े जाते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मतदाताओं की संख्या मतदान के बाद और मतगणना के पहिले बढ़ाई गई थी, उस समय उन राज्यों में एसआईआर नहीं कराई गई थी। मतगणना के पूर्व मतदाताओं की संख्या में जरूर भारी इजाफा हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर का नया फंडा शुरू कर दिया है। बिहार में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए। अब यही खेल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं अन्य राज्यों में भी खेला गया है। असम में एस आईआर नहीं कराया गया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इस बार भाजपा के निशाने पर थे। चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से चुनाव के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन बिल को महिला आरक्षण बिल से जोड़कर जो राजनीति भाजपा द्वारा की जा रही है, परिसीमन बिल गिरने के बाद इस महिला आरक्षण बिल से जोड़कर टीएमसी, कांग्रेस और डीएमके को निशाने पर लिया गया है। उसके बाद यह चर्चा होने लगी है, इस बार का नॉरेटिव महिला आरक्षण बिल है।

महिला बिल के लुढ़कने के सियासी निहितार्थ

कमलेश पांडे

इंडिया गठबंधन की विपक्षी एकजुटता ने पुन: सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की नींद उड़ा दी है। ऐसा इसलिए कि लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाने से जुड़ा था, 16 अप्रैल 2026 को वोटिंग में गिर गया। इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि न्यूनतम दो-तिहाई बहुमत (लगभग 352 वोट) की आवश्यकता थी, जो सरकार के रणनीतिकारों ने नहीं जुटा पाए। शायद पहली बार सदन में अमित शाह की रणनीति पिट गई। इसका राजनीतिक प्रभाव यह रहा कि मोदी सरकार के लिए 12 साल में पहली बड़ी संवैधानिक हार हुई है, जो विपक्ष की एकजुटता को दर्शाता है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे संविधान पर हमला बताकर कांग्रेस-विपक्ष की रणनीति की जीत घोषित की, जबकि भाजपा इसे विपक्ष विरोधी हथियार बनाने की योजना बना रही है। एक सत्ता विरोधी रणनीति के तहत जहां विपक्ष ने बिल को छलावा करार दिया, वहीं दावा किया कि यह परिसीमन और चुनावी नक्शा बदलने की साजिश है। वहीं, एक एनडीए नेता के अनुसार, बिल गिरने से सरकार अब सड़क पर विपक्ष को महिलाओं के अधिकारों के नाम पर घेरेगी।

हालांकि, सरकार ने शेष दो बिल (परिसीमन और अन्य) आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि वे मुख्य बिल पर निर्भर थे। एचएम अमित शाह और पीएम मोदी विपक्ष के विरोध को कांग्रेस के इतिहास से जोड़कर जनता में प्रचार करेंगे। यह 2029 चुनावों से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज कर सकता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में भी दिख सकता है, क्योंकि विपक्षी एकजुटता का पुन: संदेश गया है।

वहीं, मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को दोबारा लाने के लिए रणनीतिक बदलाव कर सकती है, खासकर 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में हार के बाद। समझा जाता है कि सरकार नई विधेयक रणनीति के तहत दो या तीन नए विधेयक ला सकती है: पहला लोकसभा सीटें बढ़ाकर (543 से 850 तक) 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करेगा, जिसमें एससी/एसटी के लिए सब-कोटा भी शामिल होगा। लेकिन फिर सवाल उठेगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्यों नहीं? दूसरा परिसीमन आयोग स्थापित करेगा, लेकिन इसे राज्यों के अनुमोदन से अलग रखा जा सकता है ताकि दो-तिहाई बहुमत आसान हो।

सरकार का मानना है कि विपक्ष से सहमति निर्माण के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी सभी दलों को पत्र लिखकर सर्वसम्मति की अपील कर चुके हैं, इसी सिलसिले में कांग्रेस और अन्य विपक्षियों से बातचीत जारी है। महिला कोटा बिल को 2029 चुनावों से पहले लागू करने के लिए 2011 जनगणना पर आधारित संशोधन पर जोर दिया, और नई जनगणना-परीक्षण का इंतजार खत्म किया जाएगा। इसके निमित्त संसदीय प्रक्रिया यह हैं कि विशेष सत्र बुलाकर संशोधित बिल पेश करना संभव होगा, जहां 18 घंटे लोकसभा और 10 घंटे राज्यसभा चर्चा होगी। वहीं सड़क पर प्रचार के साथ विपक्ष को ओबीसी हितों पर घेराव, जिससे राजनीतिक दबाव बनेगा। यह 2029 से पहले बहुमत जुटाने की कोशिश होगी।

इस प्रकार देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल को 2029 से पहले लागू करना संवैधानिक रूप से जटिल है, क्योंकि इसके लिए परिसीमन प्रक्रिया अनिवार्य है जो 2011 जनगणना पर आधारित होनी चाहिए। इसका संभावित विकल्प संशोधित बिल पुनर्प्रस्तावहै जिसके तहत सरकार दोबारा संशोधित विधेयक ला सकती है, जिसमें लोकसभा सीटें बढ़ाकर (543 से 850 तक) 33त्न महिला कोटा सुनिश्चित हो, लेकिन विपक्ष सहमति के बिना दो-तिहाई बहुमत मुश्किल है। इसलिए विपक्ष से सर्वसम्मति की पहल तेज है। सरकार सभी दलों से बातचीत तेज कर विशेष सत्र बुलाना, परिसीमन को अलग रखकर बिल पास करवाना, हालांकि विपक्ष इसे परिसीमन साजिश मान रहा है।

जहाँ तक व्यावहारिक बाधाओं की बात है तो परिसीमन आयोग को पब्लिक हियरिंग और प्रक्रिया में कम से कम 2-3 वर्ष लगते हैं, इसलिए 2029 चुनाव से पहले पूरा होना असंभव है। वहीं बिल गिरने से अब अगली जनगणना (2031) और उसके बाद के परिसीमन तक (2034+) देरी तय, दक्षिणी राज्यों की चिंताएं टल सकती हैं। सरकार सड़क प्रचार पर जोर देगी। वहीं विपक्ष ने लोकसभा में गिरे महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल पर मुख्य रूप से परिसीमन प्रक्रिया, ओबीसी/एससी/एसटी सब-कोटा और राजनीतिक साजिश को लेकर आपत्तियां दर्ज कीं। मुख्य आपत्तियां निम्नलिखित हैं-

पहला, परिसीमन साजिश: बिल को लोकसभा/विधानसभा सीटें बढ़ाने और 2011 जनगणना पर परिसीमन से जोड़ा गया, जिसे विपक्ष ने उत्तर भारत (विशेषकर भाजपा शासित राज्यों) को लाभ पहुंचाने वाली सीट रिबनिंग करार दिया। फलत: दक्षिणी राज्य अपनी सीटें खोने के डर से विरोधी हो गए।

दूसरा, ओबीसी/ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुपस्थिति: 33% महिला कोटा में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सब-कोटा न होने से सामाजिक न्याय का उल्लंघन ठहराया, और इसे सवर्ण महिलाओं के लिए नया मौका बताया।

तीसरा, संविधान पर हमला: राहुल गांधी ने इसे संविधान बचाओ का मुद्दा बनाया, और दावा किया कि बिल चुनावी नक्शा बदलकर विपक्ष कमजोर करेगा।

इस प्रकार राजनीतिक तर्क देते हुए विपक्ष ने इसे छलावा कहा, क्योंकि लागू होने में 2029-34 तक देरी होगी। इसलिए एकजुट होकर वोटिंग में भाजपा नीत एनडीए को हराया।

वहीं, मोदी सरकार ने विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए बिल को महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बताया, जो 25-30 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। परिसीमन पर स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने कहा कि परिसीमन 2011 जनगणना पर आधारित होगा, जो निष्पक्ष है और दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा; यह सीट वृद्धि के साथ संतुलित होगा। अमित शाह ने चुनौती दी कि यदि विपक्ष संशोधन चाहे तो सदन एक घंटा रोकें, वे तुरंत बदलाव लाएंगे।

वहीं, ओबीसी/एससी/एसटी कोटा पर जवाब देते हुए सरकार ने ओबीसी/ईडब्ल्यूएस सब-कोटा की मांग पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सरकार ने स्पष्ट कहा कि संविधान धर्म या जाति आधारित अतिरिक्त आरक्षण की अनुमति नहीं देता; इसलिए मौजूदा एससी/एसटी कोटा में महिलाओं को प्राथमिकता रहेगी। पीएम मोदी ने विपक्ष को महिलाओं के खिलाफ करार दिया, और कहा कि पंचायत स्तर पर सफलता साबित हो चुकी है।

हालांकि राजनीतिक आरोपों का खंडन करते हुए और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संविधान पर हमला सम्बन्धी दावे पर शाह ने कहा कि विपक्ष सैद्धांतिक रूप से सहमत था लेकिन वोटिंग में नकारा; अब सड़क पर इसका जवाब मिलेगा। सभी दलों से सर्वसम्मति की अपील की गई।

उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण बिल (संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026) के प्रमुख प्रावधान लोकसभा, और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करने से जुड़े हैं, जिसका

मुख्य प्रावधान इस प्रकार है-

पहला, आरक्षण का दायरा: लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों का 33त्न महिलाओं के लिए आरक्षित, जिसमें एससी/एसटी आरक्षित सीटों का भी एक-तिहाई हिस्सा शामिल है।

दूसरा, परिसीमन प्रक्रिया: 2011 जनगणना पर आधारित परिसीमन आयोग द्वारा सीटों का आवंटन और रोटेशन, जिसमें लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 तक प्रस्तावित है।

तीसरा, अवधि और प्रभावी तिथि: 15 वर्ष के लिए (संसद द्वारा विस्तार योग्य), अगले परिसीमन के बाद 2029 चुनावों से लागू होगा।

चौथा, अतिरिक्त विशेषताएं: रोटेशन आधारित सीटें प्रत्येक परिसीमन में बदलेंगी, लेकिन ओबीसी/ईडब्ल्यूएस सब-कोटा शामिल नहीं होना भी विवाद का कारण बना।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्याय: (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

इन्द्र: कश्चिद्देहधारी देवराज आसीत्तस्य त्वष्टुर-पत्येन वृत्रासुरेण सह युद्धमभूत्।

वृत्रासुरेणेन्द्रो निगलितोऽतो देवानां महद् भयमभूत्।

ते विष्णुशरणं गता:।

ईदृश्य: प्रमत्तगीतवत् प्रलपित: कथा: पुराणाभासादिष्ठ नवीनग्रन्थेषु मिथ्यैव सन्तीति भवि-द्भिर्मन्तव्यम् । कुत: । एतासामप्यलङ्कारवत्त्वात्।

अर्थात् - (दयानन्दकृत भाषानुवाद) त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने राजा इन्द्र को निगल लियाँ, तब सब देवता लोग बड़े भययुक्त होकर विष्णु के समीप में गये। यह पागलों की सी बनाई हुई पुराण कथा सब मिथ्या है, श्रेष्ठ लोगों को उचित है कि इनको कभी न मानें।

(ऋवेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ 302)

ऊपर हम ने जो विवेचन किया है उसका सार यह है कि इस वेदोक्त कथा का जहाँ वर्षा विज्ञान से सम्बन्ध है वहां वैयक्तिक इतिहास के साथ भी इसका पूरा-पूरा सम्बन्ध है।

अनादिकाल से मन्त्रद्रष्टा ऋषि लोग इस कथानक की उपर्युक्त दोनों प्रकार से व्याख्या करते आये हैं, जो दोनों ही यथार्थ हैं। जिज्ञासु जन अपनी रुचि के अनुसार इनमें से किसी भी एक को पसन्द कर सकता है। परन्तु श्रन्यतम को झुठलाने का किसी भी समालोचक को कुछ अधिकार नहीं है।

हत्या और प्रार्याश्चत्त

वृत्रासुर अत्यन्त पापिष्ठ दैत्य था, वह दैवो सम्पत्ति का अपहरण करके उसको असुरों के उपभोग में लगा रहा था। जब वह त्रिशूल उठाकर लोकत्रय को हड़प करने के लिये उद्यत हो गया तो समस्त देवताओं की रक्षा के लिये विष्णु भगवान् को सम्मति से देवराज इन्ज ने उसको मार डाला। सो इन्द्रदेव का यह कार्य किसी दृष्टि से अधर्म नहीं कहा जा तकता।

क्रमश: ..

आदि शंकराचार्य

अमृता गोस्वामी

आदि शंकराचार्य भारत के उन महान दार्शनिकों में हैं जिन्होंने संसार को मिथ्या बताकर इस चर-अचर जीव जगत में एकमात्र परब्रह्म की सत्ता को स्वीकार कर अद्वेतवाद को स्थापित किया था। शंकराचार्य के अनुसार यह संपूर्ण जगत परब्रह्म, निर्गुण निराकार है। यह जगत सत्य रूप में हमें उसी तरह जान पडता है जिस प्रकार सर्प में रज्जू यानि रस्सी का आभास होता हैं। हम अज्ञानवश इस जगत को सत्य समझ रहे हैं, जिस दिन यह भ्रांति, इस अज्ञान का पर्दा हमारी आंखों के सामने से हट जाता है, इस संपूर्ण जगत में हम सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म को ही पाते हैं।

अद्वेतवाद को हालांकि भारत में शंकराचार्य से पहले भी कई दार्शनिकों, महात्माओं ने जगत के सामने रखा था किन्तु शंकराचार्य ने इसे अपनी सरल, स्पष्ट समीक्षाओं, दार्शनिक दृष्टि और तर्क संगत रूप से ठोस और दृढ़ रूप में जगत में स्थापित किया। शंकराचार्य ने हिन्दुओं के महान ग्रंथों उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र इत्यादि पर भाष्य लिखकर अद्वेत के आधार पर उनकी सरल और सटीक व्याख्या की। भारत में सनातन धर्म और अद्वेतवाद के प्रचार प्रसार के लिए शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में चार प्रमुख मठों दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारिका शारदा मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी गोवर्द्धन मठ, और उत्तर में ज्योतिर्पीठ मठ की स्थापना की।

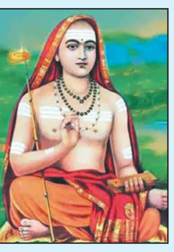

जगतगुरू आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ई.में वैशाख शुक्ल की पंचमी को हुआ था। कहा जाता है कि इनके पिता शिवगुरू और इनकी माता ने शिवजी की गहन तपस्या से पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया था जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया था किन्तु एक शर्त रखी थी कि उन्हें अपने पुत्र के लिए उसके दीर्घायु या सर्वज्ञ होने में से किसी एक को चुनना होगा। पुत्र यदि सर्वज्ञ होगा तो वह अल्पायु होगा और यदि उन्हें दीर्घायु पुत्र की कामना हो तो वह सर्वज्ञ नहीं होगा। पिता शिवगुरू ने वरदान मांगा कि मुझे सर्वज्ञ पुत्र की प्राप्ति हो। शिवजी के वरदान से समय आने पर वैशाख शुक्ल पंचमी को शिवगुरू के यहां पुत्र का जन्म हुआ उस बालक का नाम शंकर रखा गया, जिसे शिवजी का अवतार माना गया और जो बाद में जगतगुरू आदि शंकराचार्य के नाम से विख्यात हुआ।

बचपन से ही शंकराचार्य में विशिष्ट गुणों की झलक देखी जा सकती थी, छोटी सी ही उम्र में उन्होंने सारे वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत को कंठस्थ कर लिया था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात महज सात वर्ष की उम्र में शंकराचार्य ने संन्यासी बनना स्वीकार किया। शंकराचार्य की माता नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा सन्यासी बने किन्तु अपने प्रयत्नों से उन्होंने अपनी माता को इसके लिए मना लिया।

अपने जीवन में शंकराचार्य ने कई धर्म ग्रंथों की रचना की उन्होंने शिव की स्तुति में अनेक श्लोकावालियों लिखीं। शंकराचार्य की सर्वश्रेष्ठ रचना 'भजगोविंदम' में शंकराचार्य ने लोगों को यही समझाया कि अपने हर काम में गोविन्द को भजो। शंकराचार्य लिखित इस रचना में संस्कृत में वर्णित बारह स्त्रोत हैं जिसे 'द्वादश मंजरिका' भी कहा जाता है।

दिल्ली बनाम दक्षिण की लड़ाई अब तेज होगी

नीरजा चौधरी

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक का शुक्रवार को लोकसभा में गिर जाना एक बड़ी राजनीतिक घटना है. पिछले लगभग बारह साल में यह पहली बार है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की तरफ से पेश किया गया कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद में गिर गया हो. जाहिर है, इस बिल का पास न हो पाना सरकार के लिए बड़ा झटका है. हमने अभी तक देखा है कि यह सरकार बड़े नपे-तुले ढंग से अपने अभियानों को अंजाम देती रही है.

लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा की निरंतर जीत का कारण भी उसकी सटीक रणनीति रही है. अब तक अपने सभी महत्वाकांक्षी अभियानों को सफलता से अंजाम देकर वह विपक्ष की विफलता को भी बार-बार उजागर करती रही है. लेकिन लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 68 मतों से गिर गया. बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 230 मत पड़े. लोकसभा में इतने मतों का फर्क बहुत अधिक होता है. हालांकि संसद में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए दो तिहाई बहुमत जुटाना सरकार के लिए बहुत आसान नहीं था.

इसके बावजूद उसने संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश की. यह अलग बात है कि दो दिनों तक चली लंबी बहस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों के बावजूद सरकार इसे पारित कराने के लिए आवश्यक आंकड़ों का जुगाड़ नहीं कर पायी. बेशक विपक्ष इसे पारित न कराने पर अड़ा हुआ था, लेकिन सदन में बिल पारित कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की ही होती है.

जहां तक विपक्ष की बात है, तो उसने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन दिया था. लेकिन इस बार सरकार ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जिस तरह जोड़ दिया, विपक्ष उससे असहमत था. बहस के दौरान विपक्षी नेताओं ने कहा भी कि वे महिला आरक्षण के विरोधी नहीं हैं और 2023 में उन्होंने इसका समर्थन किया ही था. दरअसल परिसीमन के जरिये लोकसभा क्षेत्रों को फिर से निर्धारित किया जाना है, और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को बताया था कि परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी और इनमें सभी राज्यों की सीटों में 50 फीसदी की वृद्धि होगी.

लेकिन विपक्ष की आशंका थी कि भाजपा ने असम और जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के जरिये जो बदलाव किया, वही बदलाव वह पूरे देश में इसके जरिये करना चाहती है, जिससे देश पर भाजपा के स्थायी कब्जे की आशंका पैदा होगी. विपक्ष का यह भी मानना था कि परिसीमन के जरिये उत्तर भारत की राजनीतिक ताकत और बढ़ती, जिससे भाजपा के और मजबूती से उभर कर आने की संभावना मजबूत होती. दक्षिण के राज्य परिसीमन के मामले में पहले से ही सशंकित हैं. कांग्रेस भी कमोबेश अब दक्षिण की पार्टी ही रह गयी है, क्योंकि वहां के दो राज्यों- कर्नाटक और तेलंगाना में उसकी सरकार है, इसलिए वह भी इसके खिलाफ खड़ी हो गयी.

संविधान संशोधन विधेयक को गिराने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही, जिसने इंडिया के अपने गठबंधन सहयोगियों को इस मुद्दे पर एकजुट किया. इस मुद्दे पर कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक ने विपक्षी तालमेल का परिचय दिया, तो अखिलेश यादव ने संसद में मोर्चा संभाला. विपक्ष ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने के बजाय वह इसे भविष्य की अनिश्चितता में डाल रही है. पिछले बारह साल में पहली बार विपक्ष ने इतनी सटीक रणनीति के साथ सरकार को घेरा और एक सुर में परिसीमन को चुनावी नक्शा बदलने की साजिश बताकर वोटिंग में सरकार को पछाड़ दिया.

यह विपक्षी एकजुटता अगर बरकरार रही, तो आने वाले दिनों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है. संविधान संशोधन विधेयक का पारित न हो पाना भले ही सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका हो, लेकिन इसका असर आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति और दूसरे राजनीतिक दलों पर पड़ने वाला है. परिसीमन से उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई जोर पकड़ चुकी थी, भले ही भाजपा ने लगातार इसका खंडन किया.

अब दिल्ली बनाम दक्षिण की यह लड़ाई और तेज होगी. यह अनायास नहीं है कि संविधान संशोधन विधेयक गिरने के तुरंत बाद स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया है. और दिल्ली बनाम दक्षिण की इस लड़ाई में क्षेत्रीय उपराष्ट्रीयता को लाभ होगा. यानी आने वाले दिनों में तमिल गौरव, बांग्ला गौरव आदि मुद्दे प्रखरता से सामने आ सकते हैं. इस विधेयक को पारित न होने देने को दक्षिण भारत अपनी जीत भले ही बता रहा हो, लेकिन भविष्य में जनगणना के आधार पर जब भी परिसीमन होगा, तब दक्षिणी राज्यों को उसका नुकसान होना तय है.

इसका कारण यह है कि 2011 की जनगणना के आधार पर भाजपा दक्षिणी राज्यों में 50 फीसदी सीटों में वृद्धि की गारंटी दे रही थी, हालांकि यह गारंटी लिखित नहीं, बल्कि मौखिक ही थी. लेकिन 2026-27 या उसके बाद की जनगणना के आधार पर अगर परिसामन होगा, तो दक्षिणी राज्यों की सीटें बहुत कम हो जायेंगी, क्योंकि दक्षिणी राज्यों की आबादी में काफी कमी आयी है. इसीलिए दक्षिण की मांग है कि परिसीमन का आधार सिर्फ जनसंख्या नहीं, बल्कि उसमें राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन को भी शामिल करना चाहिए. पर इतना तो तय है कि परिसीमन का मुद्दा भविष्य में दक्षिण के राज्यों को परेशान करता रहेगा.

संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाने पर निश्चित रूप से भाजपा को उसका चुनावी लाभ मिलता. लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे में, अब भाजपा चुनावों में महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा जोर-शोर से उठायेगी. पिछले कुछ वर्षों में भाजपा की चुनावी जीतों में महिला वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वह महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या फिर बिहार. हालांकि महिला आरक्षण का मुद्दा उठाने से ही देशभर की महिला वोटरों का समर्थन उन्हें मिलेगा ही, इसकी गारंटी नहीं है.

आज की महिला वोटर बेहद स्मार्ट हैं और जब तक उन्हें कुछ ठोस नहीं मिलता, तब तक वे किसी के समर्थन में नहीं आ जातीं. हां, उत्तर भारत की महिला वोटर भाजपा के पक्ष में जरूर गोलबंद हो सकती हैं. संविधान संशोधन विधेयक के गिरने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि महिला आरक्षण लटक गया है, और मुझे तो लंबे समय तक इसके लागू होने की संभावना नहीं दिखती. यह इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है.

आज का इतिहास

1934 सर्जन की फोटो, सबसे प्रसिद्ध फोटो है जो लूप नेस मॉन्स्टर को दिखाती है। डेली मेल में प्रकाशित किया गया था।
1945 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने बर्लिन के बाहरी इलाके पर कब्जा किया।
1960 ब्रासीलिया, एक योजनाबद्ध शहर जो मुख्य रूप से वास्तुकार और उपनगरीय योजनाकार लुसियो कोस्टा द्वारा डिज़ाइन किया गया था, आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था, रियो डी जनेरियो को ब्राजील की राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था।
1962 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला विश्व मेला, 21 वीं सदी, वाशिंगटन में खोला गया।
1970 गेहूं उत्पादन पर लंबे समय से चल रहे विवाद के जवाब में, हुत नदी की रियासत ने ऑस्ट्रेलिया से अपने अलगाव की घोषणा की।
1977 मेजर जनरल जियाउर्रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति नियुक्त।
1987 श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक बम धमाके में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई।
1990 कार्टून ऑल स्टार्स टू रेस्क्यू सभी 4 टीवी नेटवर्क पर दिखाया गया है।
1991 4 वीं मैराथन विश्व कप जोन्स टोस्टियर ने हासिल किया था।
1991 सबसे बड़ी अतिरिक्त पारी की वापसी, पिट्स 11 वें तल पर 6 अंक लेकर 5 रन क्यूब लीड, पाइरेट्स भी 9 वें स्थान से नीचे 7-2 से पीछे।
1994 गोराडेज बोनसिया में जीते संकट पर सर्बियाई सेना की बमबारी के बाद 28 व्यक्ति छूट गए थे।
1994 पिकनिक को मापदंड थिएटर न्यूयॉर्क शहर में खोला गया था। यह 45 प्रदर्शनों के लिए था।
1996 न्यूयॉर्क शहर के प्राइमाउथ थिएटर में डेरिकेट बोलेंस का उद्घाटन।
1997 केन्या के लैमेक अगुला ने 101 वां बास्टन मैराथन जीता।
2004 बसरा में मिसाइल हमले में 68 लोगों की मृत्यु।
2011 शंघाई में चीनी लॉरी चालकों द्वारा बढ़ती मुद्रास्फीति के खिलाफ विरोध जारी रखा।
2012 फिलीपींस में केकड़ों की चार प्रजातियों को उज्ज्वल उद्देश्य रंग की खोज की गई थी।
2013 आकंड़ों की बाजीगरी में मशीन को मात देने वाली शकु-?तला देवी का निधन हुआ।
2016 अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मिशेल ओबामा के साथ ब्रिटेन के चार दिन की यात्रा शुरू की।

चुनौतियों के चक्रव्यूह के बीच खड़ा बिहार का नया 'सम्राट'

योगेश कुमार गोयल

बिहार की राजनीति में सत्ता का शिखर छूना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है उस शिखर पर टिके रहकर अपनी सर्वमान्यता सिद्ध करना। सम्राट चौधरी का बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में उदय राज्य के सियासी इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात माना जा रहा है। यह केवल एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में उस 'बड़े भाई' की भूमिका को आधिकारिक रूप से स्वीकार करना है, जिसका इंतजार पार्टी कार्यकर्ता दशकों से कर रहे थे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पैदा हुए राजनीतिक शून्य को भरने की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के कंधों पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह नीतीश कुमार की उस लंबी और गहरी छाया से बाहर निकल पाएंगे, जिसने पिछले दो दशकों से बिहार की राजनीति को परिभाषित किया है? यही वह कसौटी है, जिस पर अब सम्राट चौधरी को परखा जाएगा।

सम्राट चौधरी का राजनीतिक उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह उनके पिता शकुनी चौधरी की विरासत, और उनके स्वयं के आक्रामक संघर्ष, दशकों की राजनीतिक यात्रा, रणनीतिक धैर्य और समयानुकूल निर्णयों का परिणाम है। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर में जन्मे सम्राट ने बहुत कम उम्र में ही सत्ता का स्वाद चख लिया था। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने से लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर वैचारिक बदलावों और रणनीतिक फैसलों से भरा रहा है। राजद और जदयू जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ काम करने के बाद 2017 में भाजपा का दामन थामना उनके करियर का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। भाजपा ने उनमें एक ऐसे पिछड़ा नेतृत्व (ओबीसी) को देखा, जो न केवल संगठन में जान फूंक सकता था बल्कि राजद के 'माई' (एमवाई) समीकरण के सामने एनडीए के 'लव-कुश' समीकरण को मजबूती दे सकता था। विशेषकर कुशवाहा समुदाय से आने के कारण सम्राट चौधरी भाजपा के लिए सामाजिक संतुलन का सबसे सटीक मोहरा साबित हुए। भाजपा ने उन्हें न केवल स्वीकार किया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद देकर उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा भी जताया। यही भरोसा आज उन्हें मुख्यमंत्री पद तक ले आया है।

मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की नियुक्ति के साथ ही बिहार की राजनीति में एक दुर्लभ संयोग भी जुड़ा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद वह दूसरे ऐसे नेता बने हैं, जिन्होंने पहले उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी

संभाली और बाद में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। यह उपलब्धि उनके कद को तो बढ़ाती है लेकिन इसके साथ आने वाली अपेक्षाएं उनके लिए हिमालयी चुनौतियों जैसी हैं। नीतीश कुमार केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि वह बिहार के लिए एक 'इंस्टीट्यूशन' बन चुके थे। उनके 20 वर्षों के शासनकाल ने राज्य में सुशासन की एक ऐसी परिभाषा गढ़ी, जिसमें महिला सुरक्षा, सड़कें, बिजली और शराबबंदी जैसे मुद्दे हर घर से जुड़े थे। सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वे स्वयं को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में पेश करते हैं या एक ऐसी नई पहचान गढ़ते हैं, जो नीतीश के 'विकास' और भाजपा की 'वैचारिक प्रखरता' का संगम हो।

अधिकांश राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर एकमत हैं कि नीतीश कुमार जैसा सर्वमान्य नेता बनना सम्राट चौधरी के लिए रातों-रात संभव नहीं होगा। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता समाज के हर वर्ग, चाहे वह महादलित हो, अति पिछड़ा हो या आधी आबादी (महिलाएं) हो, में गहराई तक थी। सम्राट चौधरी के पास फिलहाल एक मजबूत सांगठनिक ढांचा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है लेकिन उन्हें अपनी 'आक्रामक छवि' को अब 'प्रशासकीय संयम' में बदलना होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद अब उनके हर फैसले की तुलना नीतीश कुमार के मानकों से की जाएगी। क्या वह उसी सहजता से महादलितों और अति पिछड़ों के हितों की रक्षा कर पाएंगे? क्या वह शराबबंदी जैसी पेचीदा नीतियों को लेकर जनता के बीच अपना स्पष्ट नजरिया रख पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनका उत्तर उनके कार्यकाल के शुरुआती सौ दिन ही तय करेंगे।

चुनौतियां केवल बाहर ही नहीं, गठबंधन के भीतर भी हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जदयू के भविष्य और निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में प्रवेश ने नई चर्चाओं को जन्म दिया है। जदयू के भीतर इस बदलाव को लेकर एक दबी हुई छटपटाहट है। सम्राट चौधरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि गठबंधन के सहयोगी दल खुद को उपेक्षित महसूस न करें। साथ ही, उन्हें भाजपा के भीतर भी उन वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेना होगा, जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पीछे रह गए। सम्राट चौधरी पर उनके पुराने विवादों, जैसे कम उम्र में मंत्री पद से हटाए जाने की घटना और उनके शैक्षणिक पहलुओं को लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा। एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पेशेवर छवि और शुचिता पर उठने वाले सवालों का सामना उन्हें अपनी कार्यशैली से ही करना होगा।

बिहार में 2025 का जनादेश एक तरह से 'फेयरवेल मैंडेट' जैसा रहा है, जहां जनता बदलाव की मानसिक तैयारी कर चुकी थी। सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी ताकत उनका ओबीसी समुदाय से होना और भाजपा आलाकमान का पूर्ण समर्थन है लेकिन उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा 'नीतीश कुमार का औरा' है। भाजपा ने अब तक बिहार में नीतीश कुमार के साये में राजनीति की है, अब उसे अपनी स्वतंत्र इमारत खड़ी करनी है, जिसकी नींव सम्राट चौधरी को रखनी है। यह सफर कांटों भरा है क्योंकि उन्हें न केवल विकास की रफ्तार बनाए रखनी है बल्कि बिहार की उस जटिल सामाजिक संरचना को भी साधे रखना है, जहां जाति की राजनीति कभी खत्म नहीं होती।

सम्राट चौधरी की कहानी एक ऐसे संघर्षशील नेता की है, जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने जा रही है। क्या वे बिहार को 'बीमारू' छवि से पूर्णत: मुक्त कर 'विकसित बिहार' के संकल्प को सिद्ध कर पाएंगे? यह भविष्य के गर्भ में है मगर फिलहाल बिहार की सत्ता का यह नया 'सम्राट' चुनौतियों के चक्रव्यूह के बीच खड़ा है। सम्राट चौधरी के पास अवसर भी है और चुनौती भी, अब यह उनके नेतृत्व पर निर्भर करेगा कि वे इस अवसर को इतिहास में कैसे दर्ज कराते हैं।

बिहार का नया दौर, सम्राट के सामने चुनौती विराट

पवन

राजद से जदयू के रास्ते भाजपा तक पहुंचने वाले और दो बार उपमुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री चुने जाने के साथ ही बिहार की राजनीति में निस्संदेह एक नया दौर शुरू होने जा रहा है, जिसमें भाजपा पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर राज्य का शासन संभालती नजर आएगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष का विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाते हुए ही लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के चार महीने के भीतर ही नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा में जाने की इच्छा जताने के बाद स्थितियां बदल गईं, और राज्य की सत्ता में नेतृत्व बदलाव की राह खुल गई।

अब तक राज्य के उपमुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी की यह पदोन्नति विधानसभा चुनावों में राजग की शानदार जीत के बाद गृह मंत्रालय आवंटित किए जाने के कुछ महीनों बाद हुई है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन में एक अहम बदलाव का सूचक है। सम्राट चौधरी काफी समय से भाजपा के संगठन से जुड़े रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सरकार में मंत्री व उपमुख्यमंत्री के तौर पर उनके अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को तरजीह देते हुए ही संभवत- उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। वह कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जो बिहार में ओबीसी का दूसरा सबसे बड़ा मतदाता समूह है। नीतीश कुमार खुद उन पर भरोसा जताते रहे हैं, जो गठबंधन की मजबूती को ही दर्शाता है। ऐसे में, सम्राट चौधरी का चयन जातीय संतुलन

बनाए रखने, ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने और युवा व ऊर्जावान नेतृत्व को आगे लाने की भाजपा की रणनीति का ही हिस्सा अधिक लगता है। पिछले बीस वर्षों में नीतीश कुमार की सरकार ने सड़क, बिजली, शिक्षा, महिलाओं के कल्याण और स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। राज्य में अपराध दर काफी घटी है और बुनियादी तंत्र मजबूत हुआ है। इसके बावजूद, रोजगार, शिक्षा की गुणवत्ता और उद्योग इत्यादि के क्षेत्रों में चुनौतियां मौजूद हैं। राज्य से पलायन भी रुका नहीं है। सम्राट चौधरी बतौर मंत्री राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब पूरे राज्य की जिम्मेदारी उन पर होगी। नवंबर, 2005 में नीतीश कुमार के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक उनके नाम दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड है। जाहिर है कि उनके इस्तीफे से एक युग का अंत तो होगा ही, बिहार की राजनीति और लोकनीति में एक बड़ी खाली जगह भी पैदा होगी। नीतीश कुमार राज्य की नई सरकार को सहयोग देने की बात कह चुके हैं, फिर भी देखने वाली बात होगी कि नए मुख्यमंत्री उनकी खाली जगह को कैसे भरते हैं।

न्यायपालिका को गरियाते अरविंद केजरीवाल

मनोज कुमार अग्रवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बीच हितों के टकराव को लेकर कानूनी लड़ाई और तीखी बहस चर्चा में है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में गुरुवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई में केजरीवाल के उस हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, जिसमें उन्होंने हितों के टकराव का मुद्दा उठाया था.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बीच हुआ संवाद न्यायिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कथित आबकारी घोटाला मामले में 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। मई से सितंबर 2024 के बीच उन्हें अंतरिम जमानत मिली और अंतत: रिहाई हुई। लगभग दो साल बाद फरवरी 2026 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण अरविंद केजरीवाल को तमाम आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई इस फैसले से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि अदालत ने सबूतों का सही मूल्यांकन नहीं किया, इसलिए उन्होंने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लेकिन हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के समक्ष मामला जाने से श्री केजरीवाल ने असंतोष दिखाया। अरविंद केजरीवाल अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं और इस सोमवार उन्होंने जस्टिस शर्मा के सामने ही यह मांग रखी कि वे खुद को इस मुकदमे अलग करें।

अदालत में अरविंद केजरीवाल ने तर्क दिया कि जस्टिस शर्मा ने ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है जो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों द्वारा आयोजित किए गए थे, जिससे उनके मन में न्याय मिलने को लेकर आशंका पैदा होती है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलने का डर है। श्री केजरीवाल ने कहा कि कानून

के अनुसार केवल पूर्वाग्रह की उचित आशंका ही किसी जज के केस से हटने के लिए पर्याप्त आधार है। उन्होंने जज के रिक्यूज़ल यानी खुद को मामले से अलग करने के सिद्धांत पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह जरूरी नहीं है कि कोई जज पक्षपाती हो, लेकिन अगर पार्टियों के मन में कोई वाजिब शक है तो यह रिक्यूज़ल का मामला बनता है।

इस बारे में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, मैंने खुद को सुनवाई से अलग रखने यानी रिक्यूजल से जुड़े कानून के बारे में बहुत कुछ सीखा। मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे खुद को सुनवाई से अलग रखने के लिए कहा है। लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छा फैसला दे पाऊंगी।

अब गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने एक और नया हलफनामा अदालत में दाखिल किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चे केंद्रीय सरकारी पैनलों में हैं, यानी वरिष्ठ अधिवक्ता और मोदी सरकार के सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता के अधीन काम कर रहे हैं। तुषार मेहता उन्हें मामले सौंपते हैं। ऐसी स्थिति में माननीय जज के लिए तुषार मेहता के खिलाफ कोई आदेश पारित करना कठिन होगा। इसलिए अन्य कारणों के साथ-साथ, माननीय न्यायाधीश को इस मामले से स्वयं को अलग कर तेना चाहिए। हलफनामे में दावा किया गया है कि चूंकि केंद्र सरकार इस मामले में एक पक्ष है, इसलिए इससे निष्पक्ष प्रभावित हो सकती है। याचिका में कहा गया है कि म होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी हिए। जज साहिबा के करीबी सदस्य उस पक्ष (केंद्र सरकार के साथ पेशेवर रूप से जुड़े हों जिससे संबंधित मामला सुना जा रहा है, तो यह उचित निष्पक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है।

गुरूवार को लगभग 5 मिनट तक चली इस सुनवाई में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है. उन्होंने कहा, हम इस हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं, लेकिन इस पर अब कोई नई बहस नहीं होगी. मैं इस मामले को अब दोबारा नहीं खोलूंगी. इसका मतलब है कि कोर्ट अब सीधे अपना फैसला सुनाएगी. अब इस मामले में आगे क्या होता है और किस तरह दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई होती है, क्या जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगी या श्री केजरीवाल की मांग सुनते हुए अलग हो जाएंगी, यह देखना दिलचस्प होगा। मगर इतना तय है कि अब यह मामला कानूनी और राजनैतिक पहलू से बढ़कर भारतीय लोकतंत्र में संस्थाओं के बीच संतुलन की परीक्षा बन चुका है। इस मामले ने न्यायपालिका, कार्यपालिका के बीच शक्ति-संतुलन, जांच एजेंसियों के राजनैतिक इस्तेमाल और विधिक प्रक्रिया की शुचिता और सक्रियता से जुड़े गंभीर प्रश्नों को जन्म दिया है। इस मामले का अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, इतना तय है कि यह आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक बहसों को दिशा देगा और भावी सुनवाइयों के लिए मिसाल भी बनेगा।

होर्मुज, सुएज और बाब अल मंदेब, दुनिया की सांस इन्हीं रास्तों से चलती है

जाहिद खान

सबसे पहले बात होर्मुज की। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच ये पतली सी पट्टी है लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। दुनिया का करीब 20त्न तेल यहीं से गुजरता है। रोजाना लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से निकलता है। ईरान एक तरफ है और ओमान दूसरी तरफ। जब भी ईरान और अमेरिका या इस्राइल के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले इसी रास्ते का नाम सामने आता है।

1980 से 1988 के बीच ईरान-इराक जंग में यही इलाका टैंकर वॉर का मैदान बना। दोनों तरफ से तेल ले जाने वाले जहाजों पर हमले हुए। नतीजा ये हुआ कि तेल की कीमतें बढ़ीं और पूरी दुनिया परेशान हो गई। फिर 2019 में भी कई तेल टैंकरों पर हमले हुए। अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाए, ईरान ने इनकार किया, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि दोनों आमने-सामने आ गए। उस समय भी दुनिया को यही डर सताने लगा था कि अगर होर्मुज बंद हुआ तो क्या होगा।

और अब जो मौजूदा हालात बने हैं, उनमें ये खतरा फिर से सामने खड़ा है। अमेरिका की तरफ से समुद्री रास्तों पर दबाव बढ़ाने की बातें, ईरान की तरफ से जवाबी चेतावनियां और इस्राइल के साथ बढ़ता तनाव। इन सबके बीच होर्मुज फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। ईरान कई बार साफ कह चुका है कि अगर उस पर सीधा दबाव बढ़ा तो वह इस रास्ते को बंद करने का कदम भी उठा सकता है।

साफ बात है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है क्योंकि अगर होर्मुज पर आवाजाही रुकती है तो सिर्फ खाड़ी देशों का नहीं, पूरी दुनिया का तेल रुक जाता है। तेल महंगा होता है, ढुलाई महंगी होती है और असर हर देश के आम आदमी तक पहुंचता है। यानी होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज है और जब भी जंग का ताप बढ़ता है, सबसे पहले यही नब्ज कांपने लगती है। अब सुएज नहर को समझो। ये मिस्र में है और यूरोप को सीधे एशिया से जोड़ती है। दुनिया का करीब 10त्न व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है और हर साल लगभग 20,000 जहाज यहां से निकलते हैं।

1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने सुएज नहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और इस्राइल ने मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया। इसे सुएज संकट कहा जाता है। जंग हुई, लेकिन

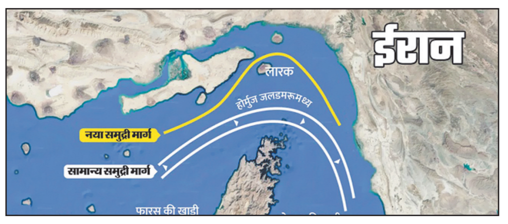

अंतरराष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ा और आखिरकार इन तीनों को पीछे हटना पड़ा और नहर फिर मिस्र के पास ही रही, लेकिन असली बड़ा झटका 1967 में आया, जब इस्राइल और अरब देशों के बीच छह दिन की जंग हुई। इस जंग में इस्राइल ने मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप अपने कब्जे में ले लिया और सुएज नहर का इलाका सीधे युद्ध की रेखा बन गया। हालात इतने खराब हो गए कि नहर पूरी तरह बंद कर दी गई और ये बंदी पूरे आठ साल चली यानी 1967 से 1975 तक।

इस दौरान नहर में फंसे कई जहाज वर्षों तक वहीं खड़े रहे, जिन्हें येलो फ्लीट कहा गया। दुनिया का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ और जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर लगाना पड़ा, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए। फिर 1973 में एक और जंग हुई, जिसे योम किप्पुर वॉर कहा जाता है। इसके बाद धीरे-धीरे हालात बदले। 1975 में मिस्र ने सुएज नहर को फिर से खोल दिया। बाद में 1978 में कैंप डेविड समझौता हुआ और 1979 में मिस्र ने औपचारिक तौर पर इस्राइल को मान्यता दी। इसके बदले में इस्राइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को वापस कर दिया।

1967 की अरब-इस्राइल जंग के बाद ये नहर पूरे आठ साल के लिए बंद हो गई। 1975 में जाकर फिर से खुली। सोचो, एक रास्ता बंद हुआ और पूरी दुनिया के जहाजों को अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाना पड़ा। खर्च बढ़ा, समय बढ़ा, असर हर जगह पड़ा। 2021 में एक और घटना हुई जब 'एवर गिवन' नाम का एक बड़ा जहाज नहर में फंस गया। सिर्फ छह दिन के जाम ने दुनिया को दिखा दिया कि ये रास्ता कितना जरूरी है। हर दिन करीब 9 से 10 बिलियन डॉलर का व्यापार रुक गया।

अब आते हैं बाब अल मंदेब पर। ये लाल सागर और अरब सागर के बीच का संकरा रास्ता है, जो यमन और जिबूती के बीच पड़ता है। देखने में छोटा लगता है, लेकिन अहमियत बहुत बड़ी है। दुनिया का करीब 10त्न समुद्री तेल और लगभग 12त्न कारोबार इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन करीब 6 से 7 मिलियन बैरल तेल और बड़ी संख्या में माल से भरे जहाज यहां से निकलते हैं।

यही रास्ता सुएज नहर से जुड़ता है, इसलिए अगर बाब अल मंदेब पर असर पड़ा तो सुएज भी अपने आप प्रभावित हो जाता है। मतलब एक झटका और पूरी सप्लाई की पूरी कड़ी हिल जाती है। इतिहास में भी ये इलाका कभी पूरी तरह शांत नहीं रहा। 1973 की अरब-इस्राइल जंग के दौरान इस रास्ते को बंद करने की कोशिश की गई थी ताकि इस्राइल तक जरूरी सामान न पहुंच सके। तब भी दुनिया ने देखा कि ये रास्ता बंद करने का असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया तक जाता है।

लेकिन हाल के वर्षों में इसकी अहमियत और खतरा दोनों बढ़ गए हैं। यमन की जंग के बाद हूती लड़ाके लगातार इस रास्ते को निशाना बना रहे हैं। 2016 में अमेरिका के एक युद्धपोत पर मिसाइल दागी गई थी, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी हमला किया।

फिर 2023 और 2024 में हालात और बिगड़ गए। हूती लड़ाकों ने कई बड़े मालवाहक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, कुछ जहाजों को कब्जे में भी लिया। इसके बाद दुनिया की कई बड़ी जहाजरानी कंपनियों ने इस रास्ते से अपने जहाज हटाने शुरू कर दिए।

नतीजा ये हुआ कि जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ा। इससे हर यात्रा में करीब 10 से 15 दिन ज्यादा लगने लगे और ईंधन का खर्च भी काफी बढ़ गया। बताया जाता है कि इस वजह से समुद्री ढुलाई की लागत करीब 30त्न तक बढ़ गई और कई देशों में रोजमर्रा के सामान महंगे होने लगे। यानी यमन की जंग का असर सीधे दुनिया के बाजार तक पहुंच गया। आज हालत ये है कि बाब अल मंदेब सिर्फ एक समुंद्री रास्ता नहीं रहा, ये एक दबाव बनाने का जरिया बन गया है। जो इसे प्रभावित करता है, वो दुनिया की सप्लाई को प्रभावित कर सकता है।

इन तीनों रास्तों की कहानी एक जैसी है। जहां से दुनिया का सामान गुजरता है, वहीं सबसे ज्यादा तनाव भी होता है। क्योंकि जिसे इस पर कंट्रोल मिला, उसे भरपूर ताकत मिलती है।

होर्मुज, सुएज और बाब अल मंदेब, ये तीनों सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं बल्कि दुनिया की सप्लाई लाइन हैं। यहां जरा सा भी तनाव होता है तो असर तेल की कीमतों से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक पहुंच जाता है। इतिहास बार-बार यही बताता है कि जब ये रास्ते जंग का मैदान बने तो नुकसान सिर्फ लड़ने वालों का नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ी।

पाकिस्तान का दोहरा चरित्र!

नीरज कुमार दुबे

पाकिस्तान की विदेश नीति को अगर सीधे शब्दों में समझना हो तो यह साफ दिखता है कि वह एक साथ दो खेल खेलता है। सामने दोस्ती, पीछे साजिश यही उसकी पहचान बन चुकी है। हाल के घटनाक्रम ने इसे और उजागर कर दिया है। पिछले साल जून में जब पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी तो इसके पीछे गहरी रणनीति छिपी थी। इस एक बैठक ने दिखा दिया था कि पाकिस्तान कैसे एक तरफ खुद को सहयोगी बताता है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अपने मतलब का खेल खेलता रहता है।

बताया जाता है कि इस मुलाकात में ईरान के मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई थी। यह भी चर्चा में रहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के ठिकानों के इस्तेमाल की संभावना टटोली। इससे भी गंभीर आरोप यह है कि पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु ठिकानों से जुड़ी जानकारी अमेरिका को उपलब्ध कराई, जिसके आधार पर पिछले साल ही ईरान में अमेरिकी हमला हुआ था। यह न केवल विश्वासघात है बल्कि मुस्लिम दुनिया में भी एक गहरी दरार का संकेत देता है।

देखा जाये तो पाकिस्तान और ईरान के संबंध कभी भी सहज नहीं रहे। एक ओर धार्मिक मतभेद हैं जहां सुन्नी और शिया का सवाल हमेशा तनाव का कारण बना रहा, वहीं दूसरी ओर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है। पाकिस्तान खुद को इस्लामी दुनिया की एकमात्र परमाणु शक्ति के रूप में देखता रहा है और वह नहीं चाहता कि कोई और मुस्लिम देश इस श्रेणी में आए। ऐसे में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान के लिए असहजता का कारण बनता है। यही वजह है कि पाकिस्तान खुले मंच पर भले ही तटस्थता की बात करे, लेकिन पर्दे के पीछे वह अलग खेल खेलता दिखता है।

यह दोहरापन सिर्फ ईरान के मामले तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान एक ओर अमेरिका के साथ खुफिया सूचनाएं साझा करता है, वहीं दूसरी ओर खुद को शांति दूत के रूप में प्रस्तुत करता है। ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध में पाकिस्तान ने शांति वार्ता कराने की पहल का दिखावा किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में शांति की कोशिश थी या अपनी छवि सुधारने का प्रयास था?

इस पूरे खेल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक तरफ वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांति और सहयोग की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार की नीतियां और फैसले पाकिस्तान की दोहरी रणनीति को मजबूत करते हैं। यह एक तरह का सुनियोजित भ्रम है जिसमें दुनिया को एक चेहरा दिखाया जाता है और दूसरा चेहरा छिपा रहता है।

साथ ही अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध भी इस संदर्भ में दिलचस्प हैं। डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपने पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा कर चुके हों, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उनका रुख बदला हुआ नजर आता है। इसकी एक वजह यह भी है कि ट्रंप परिवार का पाकिस्तान में आर्थिक निवेश है। ऐसे में रणनीतिक हित और निजी हित एक दूसरे में घुलते नजर आते हैं।

यही सबसे खतरनाक पहलू है कि अमेरिका पाकिस्तान के इस खुले दोहरे चरित्र को भलीभांति समझता है, फिर भी जानबूझकर उसे नजरअंदाज करता है। यह कोई मजबूरी नहीं बल्कि सोची समझी चाल है। हालिया संघर्षविराम का श्रेय पाकिस्तान को देना इसी खेल का हिस्सा है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान एक तरफ आग को हवा देता है और दूसरी तरफ खुद को बुझाने वाला बताता है, फिर भी वह इस्लामाबाद को आगे करता है ताकि अपने रणनीतिक हित साध सके। दूसरी ओर पाकिस्तान इस मौके को ऐसे भुनाता है मानो वह दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत हो, जबकि हकीकत यह है कि वही पर्दे के पीछे हालात बिगाड़ने में भी शामिल रहता है। यह पूरी कहानी एक सुनियोजित नाटक की तरह है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान दोनों अपने अपने किरदार निभा रहे हैं और दुनिया को गुमराह किया जा रहा है।

यहां असल सवाल यह है कि क्या दुनिया इस दोहरे खेल को समझ रही है? पाकिस्तान लंबे समय से इसी रणनीति पर काम करता आया है। अफगानिस्तान के मामले में भी उसने एक तरफ अमेरिका का साथ दिया और दूसरी तरफ तालिबान को समर्थन दिया। अब वही नीति ईरान के संदर्भ में दिखाई दे रही है।

हनुमानजी की 11 मुखी मूर्तियां करती हैं अलग-अलग मनोकामनाओं की पूर्ति

प्रत्येक व्यक्ति को हनुमानजी की भक्ति करना चाहिए। कलियुग में हनुमान ही एकमात्र जाग्रत देव हैं। उनका चारों युग में प्रताप है। उनकी भक्ति से व्यक्ति के भीतर साहस और आत्मविश्?वास का संचार होता है। हनुमानजी की भक्ति हर संकट से बचाती है। भक्तों ने अपनी भक्ति के चलते हनुमानजी के अलग-अलग रूप को पूजनीय बनाया है। कहते हैं कि हनुमानजी की भिन्न-भिन्न मूर्तियों की उपासना से भिन्न-भिन्न फल की प्राप्ति होती है। वैसे हनुमाजी की और भी मुखों वाली मूर्तियां हैं लेकिन हम जानते हैं 11 मुख वाले हनुमाजी की मूर्तियों की उपासना के लाभ।

● पूर्वमुखी

पूर्व की तरफ जो मुंह है उसे 'वानर' कहा गया है। जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यो के तेज समान हैं। इनका पूजन करने से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। इस मुख का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है।

● पश्चिममुखी

पश्चिम की तरफ जो मुंह है उसे 'गरूड़' कहा गया है। यह रूप संकटमोचन माना गया है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ अजर-अमर हैं उसी तरह इनको भी अजर-अमर माना गया है।

● उत्तरामुखी हनुमान

उत्तर दिशा देवताओं की मानी जाती है। यही कारण है कि शुभ और मंगल की कामना उत्तरामुखी हनुमान की उपासना से पूरी होती है। उत्तर की तरफ जो मुंह है उसे 'शूकर' कहा गया है। इनकी उपासना करने से अबाध धन-दौलत, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, लंबी आयु तथा निरोगी काया प्राप्त होती है।

● दक्षिणामुखी हनुमान

दक्षिण की तरफ जो मुंह है उसे 'भगवान नृसिंह' कहा गया है। यह रूप अपने उपासको को भय, चिंता और परेशानीयों से मुक्त करवाता है। दक्षिण दिशा में सभी तरह की बुरी शक्तियों के अलावा यह दिशा काल की दिशा मानी जाती है। यदि आप अपने घर में उत्तर की दीवार पर हनुमानजी का चित्र लगाएंगे तो उनका मुख दक्षिण की दिशा में होगा। दक्षिण में उनका मुख होने से वह सभी तरह की बुरी शक्तियों से हमें बचाते हैं। इसलिए दक्षिणामुखी हनुमान की साधना काल, भय, संकट और चिंता का नाश करने वाली होती है।

● ऊर्ध्वमुख

हनुमानजी का ऊर्ध्वमुख रूप 'घोड़े' के समरूप है। यह स्वरूप ब्रह्माजी की प्रार्थना पर प्रकट हुआ था। मान्यता है कि हयग्रीवदैत्य का संहार करने के लिए वे अवतरित हुए थे।

● पंचमुखी हनुमान

राम लक्ष्मण को अहिरावण से मुक्त कराने के लिए हनुमानजी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। पांचों दीपक को एक साथ बुझाने पर अहिरावन का वध हो जाएगा इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख।

● एकादशी हनुमान

श्रीहनुमानजी रुद्र यानी शिव के ही ग्यारहवें अवतार माने गए हैं। ग्यारह मुख वाले कालकारमुख नामक एक भयानक बलवान राक्षस का वध करने के लिए श्रीराम की आज्ञा से हनुमानजी ने एकादश मुख रूप ग्रहण करके चैत्र पूर्णिमा (हनमान जयंती) को शनिश्चर के दिन उस राक्षस का उसकी सेना सहित वध कर दिया था। एकादशी और पंचमुखी हनुमान जी पूजा से सभी देवी और देवताओं की उपासना के फल मिलते हैं।

● वीर हनुमान

जैसा की नाम से ही विदित है कि इस नाम से हनुमानजी की प्रतिमा की पूजा जीवन में साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास प्रदान कर सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करती है।

● भक्त हनुमान

राम की भक्ति करते हुए आपने हनुमानी का चित्र या मूर्ति देखी होगी। इस चित्र या मूर्ति की पूजा से जीवन के लक्ष्य को पाने में आ रहीं अड़चनें दूर होती है। साथ ही यह भक्ति जरूरी एकाग्रता और लगन देने वाली होती है। इस मूर्ति या चित्र में हनुमानजी हाथ में करताल लेकर राम की भक्ति करते नजर आएंगे।

● दास हनुमान

हनुमानजी रामजी के दास हैं। सदा रामकाज करने को आतुर रहते हैं। दास हनुमान की आराधना से व्यक्ति के भीतर सेवा और समर्पण की भावना का विकास होता है। धर्म, कार्य और रिश्तों के प्रति समर्पण और सेवा होने से ही सफलता मिलती है। इस मूर्ति या चित्र में हनुमानजी प्रभु श्रीरामजी के चरणों में बैठे हुए हैं।

● सूर्यमुखी हनुमान

शास्त्रों के मुताबिक श्रीहनुमान के गुरु सूर्यदेव हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होकर जगत को प्रकाशित करता है। सूर्यमुखी हनुमान की उपासना से ज्ञान, विद्या, ख्याति, उन्नति और सम्मान मिलता है। सूर्यमुखी हनुमान को ही पूर्वमुखी हनुमान कहते हैं। कहा जाता है कि अगर पंचमुखी हनुमान जी की पूजा सही तरीके व सम्मान से नहीं की जाए, तो इसको भूलकर भी घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति घर में रखने के विशेष नियम बताए गए हैं। दरअसल, पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप अधिक ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। जो घर के सामान्य वातावरण के लिए अनुकूल नहीं होता है।

घर में क्यों नहीं रखनी चाहिए पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर

हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप उग्रता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसको घर में रखने से घर का माहौल अशांत और उग्र हो सकता है। खासकर यदि पंचमुखी हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा न की जाए। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना आसान नहीं होता है, इनकी पूजा के कुछ विशेष नियम होते हैं। ऐसे में सब लोग इन नियमों का सभी लोग पालन नहीं कर पाते हैं। अगर पंचमुखी हनुमान जी की पूजा में कोई कमी होती है, तो इससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है।

कहां रखनी चाहिए पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति

पंचमुखी हनुमान जी की पूजा मंदिरों में की जाती है। जहां पर उनकी ऊर्जा का प्रबंधन सही तरीके से हो सकता है।

पंचमुखी हनुमान की मूर्ति मंदिरों में रखना सबसे अच्छा माना जाता है।जिससे कि उनकी नियम से पूजा की जा सके। कुछ व्यावसायिक स्थलों पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखने से बिजनेस में मुनाफा हो सकता है, साथ ही यह मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा से भी रखा करती है।

पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के लिए विशेष स्थान

बता दें कि घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को रखने से सही दिशा और स्थान का चयन जरूर कर लें। ज्योतिष और वास्तु के मुताबिक गलत दिशा और स्थान पर हनुमान जी के इस पवित्र स्वरूप की स्थापना करने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा की जगह वास्तु दोष पैदा हो सकता है। अक्सर लोग पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को घर के मुख्य द्वार पर लगा देते हैं। लेकिन यह स्थान उपयुक्त नहीं माना जाता है। ऐसा करने से उनकी ऊर्जा का सही से उपयोग नहीं हो पाता है और अंजाने में मूर्ति का अपमान भी हो सकता है।

पंचमुखी हनुमान को माना जाता है साहस, शक्ति और रक्षा का प्रतीक

हिंदू धर्म में पंचमुखी हनुमान को साहस, शक्ति और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी के पांच मुखों वाली मूर्ति विशेष रूप से पूजनीय होती है। हनुमान जी के पांच मुख अलग- अलग देवताओं के रूप को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बहुत से लोग घरों में भी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं।हनुमान जी के पांच मुख उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा हनुमान जी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सनातन धर्म में तुलसी पूजा का महत्व

सनातन धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस पौधे में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है और धन लाभ के योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तुलसी की मंजरी से जुड़े उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही धन से जुड़ी समस्या दूर होती है।

श्रीहरि होंगे प्रसन्न–यदि आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद प्रभु की पूजा करें और उनके चरणों में तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस उपाय को विधिपूर्वक करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामना पूरी होती है।

आर्थिक तंगी होगी खत्म–अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो तुलसी की मंजरी और दूध से भगवान विष्णु का विधिपूर्वक अभिषेक करें। साथ ही जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी जल्द खत्म होती है और हमेशा पैसों से तिजोरी भरी रहती है।

कभी खाली नहीं होगी तिजोरी

तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं। कुछ समय के बाद इसे पर्स या फिर तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से तिजोरी पैसों से कभी खाली नहीं होती है और धन लाभ के योग बनते हैं।

सुख-समृद्धि में होगी वृद्धि–अगर आप जीवन में दुख और संकट का सामना कर रहे हैं, तो पूजा के दौरान तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस उपाय को करने से जीवन के सभी तरह के दुख संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। सनातन धर्म में तुलसी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसकी पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। तुलसी की मंजरी का उपयोग विभिन्न ज्योतिषीय उपायों में किया जाता है, जिससे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। इस लेख में हम तुलसी पूजा के महत्व और इसके ज्योतिषीय लाभों के बारे में विस्तार से जानेंगे।

सनातन धर्म में तुलसी का है विशेष महत्व

सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा, तुलसी को लेकर तमाम मान्यताएं भी हैं। , तुलसी के पास छिपकली का दिखना शुभ संकेत है। माना जाता है कि, यदि तुलसी के पौधे के पास छिपकली दिखाई देती तो इसका मतलब है कि धन-लाभ और समृद्धि हो सकती है।

यह घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाने वाला माना जाता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के पास छिपकली का दिखना घर में सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने और अच्छे समय के आगमन का प्रतीक माना जाता है। अगर तुलसी पर छिपकली दिखाई दे और वह सुरक्षित रूप से चली जाए, तो इसे शुभ माना जाता है और यह संकेत करता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। कुछ संस्कृतियों में, छिपकली को बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए, तुलसी के पास छिपकली का दिखना घर और परिवार की सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लेकिन यदि छिपकली बार-बार तुलसी के पौधे पर आती दिखे, तो यह घर में कलह या विवाद का संकेत हो सकता है। तुलसी में मंजरी आने का मतलब है कि जीवन में आने वाले संकटों से निजात मिलेगी। इसके लिए तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उस स्थान पर रख दें, जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा.

घर से निकलने से पहले हथेली पर लगाएं गुलाब का इत्र

● कुछ ही हफ्ते में खत्म होंगी ये 2 परेशानियां

वास्तु शास्त्र के हिसाब से हफ्ते के सातों दिन किसी ना किसी ग्रह से जरूर जुड़े होते हैं। अगर दिन के हिसाब से हम छोटे-छोटे उपाय करने लगे तो इसका असर जिंदगी में धीरे-धीरे दिखने लगेगा। शास्त्र के हिसाब से शुक्रवार का दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वहीं इस दिन का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। शास्त्र में शुक्र को लग्जरी, प्यार और पैसा देने वाला ग्रह कहा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनकी जिंदगी में इन चीजों को कमी कभी नहीं होगी। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह उतना मजबूत नहीं हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शुक्रवार के दिन एक आसान सा उपाय कर लिया जाए तो तमाम लोग इससे होने वाले फायदे का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये उपाय क्या है और इससे क्या-क्या लाभ हमें मिल सकते हैं?

शुक्र ग्रह का मजबूत और कमजोर होना

शुक्रवार और शुक्र ग्रह का बेजोड़ संबंध है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह के मजबूत और कमजोर होने से इसका असर सुख-सुविधाओं, रिश्तों और पैसों पर पड़ता है। जब शुक्र मजबूत होता है तो जिंदगी में प्यार और पैसे की कोई कमी नहीं होती है। जिनका ये ग्रह मजबूत होता है वो लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। वहीं इसके कमजोर होते ही रिश्तों में मनमुटाव की स्थिति बनती है और पैसों की तंगी परेशान करती है।

हथेली पर लगा लें गुलाब का इत्र

अगर आपको अपना शुक्र ग्रह मजबूत करना है तो शुक्रवार के दिन एक आसान सा उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह के उपाय के तौर पर बताया जाता है कि गुलाब का इत्र से काफी लाभ मिल सकते हैं। अगर घर से निकलने से पहले हथेली पर थोड़ा सा इत्र लगा लिया जाए तो इसे काफी शुभ माना जाता है। हालांकि इत्र को लगाने का भी नियम है।

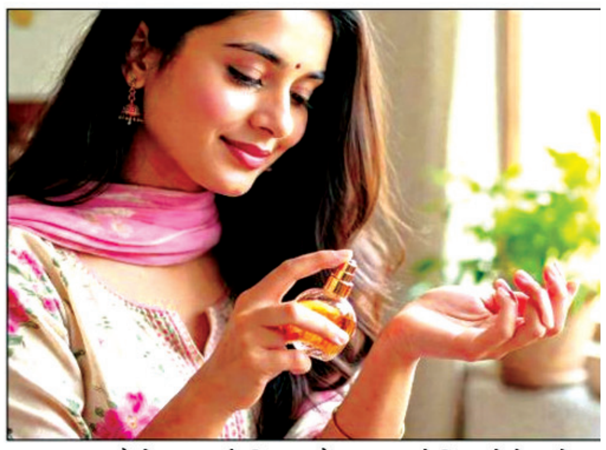

रोज-रोज झगड़ों की वजह हो सकते हैं यह वास्तु दोष

घर में किसी न किसी बात पर अक्सर झगड़े होते रहते हैं। इसके लिए कहीं वास्तुदोष तो जिम्मेदार नहीं है। हमारे जीवन में वास्तु का विशेष महत्व होता है। वास्तु के उपाय से निजी जीवन और प्रोफेशनल लाइफ में फैली तमाम तरह की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। यह कुछ ऐसे ही टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर सभी तरह की परेशानियों से पीछा छुड़ाया जा सकता है।

वास्तु शास्त्र में ईशान कोण का विशेष महत्व होता है। इस दिशा को बहुत ही शुभ माना जाता है। घर का ईशान भाग उठा हुआ नहीं होना चाहिए। घर के इस हिस्से में यह दोष होने से पिता-पुत्र के बीच दूरियां बढ़ती है।

घर के उत्तर पूर्व कोने में स्टोर रूम नही बनवाना चाहिए ऐसा करने से भी घर के सदस्यों के बीच लड़ाई-झगड़ा होता है।

वास्तु अनुसार उत्तर पूर्वी दिशा में रसोई घर या शौचालय होने पर घर के सदस्यों की बीच में मनमुटाव बना रहता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्वी दिशा में रसोईघर या शौचालय नहीं होना चाहिए।

ईशान कोण पर बिजली के उपकरणों को रखने से पिता पुत्र के बीच अनबन बनी रहती है। घर के उत्तर पूर्वी दिशा में इन चीजो को नही रखना चाहिए।

वास्तु के अनुसार घर के उत्तर-पूर्व दिशा में कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए इससे घर के सदस्यों के बीच में मनमुटाव रहता है।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं तथा इन्हें अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा।

वास्तु में दिशाओं का महत्व

● आपके दैनिक जीवन ● स्वास्थ्य और धन पर दिशाओं का चमत्कारी प्रभाव

वास्तु में दिशाओं का महत्व केवल घर या सामान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर मनुष्यों पर भी पड़ता है। कोई व्यक्ति किस दिशा में सोता है, जागता है, खाता है या काम करता है, इन सबका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है।

वास्तुशास्त्र में अलग-अलग दिशाएँ अलग-अलग ऊर्जाओं से जुड़ी होती हैं। ये दिशाएँ केवल घर की नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन की दिशा भी तय करती हैं। जिस दिशा में हम रहते, काम करते, सोते या पूजा करते हैं, उसका सीधा असर हमारी सोच, स्वास्थ्य, धन और रिश्तों पर पड़ता है। दिशाओं का असर केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी होता है। सूर्य की गति, हवा का प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र सीधे तौर पर स्वास्थ्य और मूड को प्रभावित करते हैं।

पूर्व दिशा –पूर्व दिशा को उन्नति, अध्यात्म और ज्ञान की दिशा माना गया है। यह दिशा सूर्य की दिशा है। इस दिशा की ऊर्जा का असर बुद्धि, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और करियर में उन्नति पर पड़ता है। इसलिए, इस दिशा में अध्ययन कक्ष, मुख्य द्वार, बच्चों का कमरा होना बेहद शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा में खिड़की या पूजा स्थान होने से सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति मिलती है। इस दिशा में दोष होने पर निर्णय क्षमता कमजोर और अवसर हाथ से निकलना जैसी **पश्चिम दिशा**–यह लाभ और संतुलन की दिशा मानी जाती है। इस दिशा की ऊर्जा से मेहनत का फल, धैर्य और सामाजिक मान-सम्मान मिलता है। सूर्यास्त की ऊर्जा मन को शांत करती है और दिन का संतुलन देती है। इस दिशा में भोजन कक्ष बनाने या बच्चों का कमरा बनाने की सलाह दी जाती है। पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष या बैठक कक्ष होने से पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। इस दिशा में दोष होने पर काम में देरी या अपेक्षित परिणाम न मिलने जैसी समस्याएं भुगतनी पड़ती है।

उप-दिशाओं का असर

अग्नि कोण

यह दिशा ऊर्जा, स्वास्थ्य और पाचन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए, इस दिशा में रसोई बनानी की सलाह दी जाती है। इस दिशा में दोष होने पर क्रोध या वैवाहिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

दक्षिण दिशा -

यम की दिशा होने के कारण इसे अक्सर गलत समझा जाता है, जबकि यह स्थिरता और शक्ति की दिशा है। लोगों को इस दिशा में मास्टर बेडरूम बनाने की सलाह दी जाती है।

उत्तर दिशा

उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। इसलिए, यह धन, करियर और अवसर की दिशा भी मानी जाती है। यह दिशा तिजोरी रखने, ऑफिस या वर्कस्टेशन के लिए बिलकुल सही मानी जाती है। इससे आर्थिक स्थिरता, व्यापार में वृद्धि और नए अवसर मिलते हैं। उत्तर चुंबकीय ऊर्जा का स्रोत है, जो मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता को बढ़ाती है। उत्तर दिशा में मुख्य द्वार या ऑफिस होने से आर्थिक वृद्धि और नए अवसर मिलते हैं। अगर इस दिशा में दोष हो, तो आय में रुकावट और कर्ज की स्थिति पैदा हो जाती है।

पितृदोष से लेकर कई ग्रह दोषों का निवारणकरती है गाय

गााय का वर्णन हमरे पुराणोंमें है। इसके अलावा ज्योतिष में भी गायों को महत्व दिया गया है। शिवपुराण एवं स्कन्दपुराण में कहा गया है कि गोसेवा और गोदान से यमराज का भय नहीं रहता है। इसलिए हमें गायों की सेवा करनी चाहिए। शुभ कार्यों के लिए गोधूलि वेला खास बताई गई है। मंगल कार्यों के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त जब गाय चारा चरकर जंगल से वापस आती हैं, उस समयको गोधूलिवेला कहा जाता है। गाय को ज्योतिष में भी खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर गाय को रोटी खिलाएं और गाय की सेवा करें, तो कई ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। यहां पढ़ें गाय से किन जयोतिष दोषों में लाभ होता है। अगर आप किसी शुभ कार्य के लिएजा रहे हैं, तो आपको बछड़े को दूध पिताली हुई गाय मिल जाए, तो समझ लें कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, वो सफल हो जाएगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री मोदी ने जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि दी

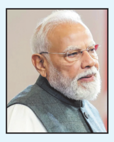

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बसव जयंती के अवसर पर सोमवार को जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि न्यायपूर्ण समाज के उनके दृष्टिकोण और लोगों को सशक्त बनाने के उनके अटूट प्रयासों से हम सभी को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''बसव जयंती के इस विशेष अवसर पर जगद्गुरु बसवेश्वर और उनके उपदेशों को नमन। एक न्यायपूर्ण समाज का उनका सपना और जनसशक्तीकरण के उनके अटूट प्रयास हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।'' बसवेश्वर, 12वीं शताब्दी के कवि-दार्शनिक और लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे, उन्हें बसवन्ना के नाम से भी जाना जाता है। बसव जयंती मुख्य रूप से 12वीं सदी के महान समाज सुधारक, दार्शनिक और कवि महात्मा बसवेश्वर (जिन्हें %बसवन्ना% भी कहा जाता है) के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। यह त्योहार मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है।

राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन आज

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बालोतरा जिले में स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। यह राजस्थान और देश दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। पचपदरा (बालोतरा जिला) में भव्य उद्घाटन समारोह की तैयारियों के मद्देनजर, जिला प्रशासन ने सार्वजनिक सभा स्थल पर व्यापक और आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए लोगों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। कार्यक्रम में आने वाली भारी भीड़ को राहत देने के लिए मिस्ट सिस्टम, डेजर्ट कूलर, पर्याप्त पेयजल और छाछ वितरण जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर पहली बार मिस्ट सिस्टम लगाया जा रहा है। इस आधुनिक व्यवस्था के तहत हवा में पानी की बारीक बूंदें छिड़की जाएंगी, जिससे आसपास का तापमान प्रभावी रूप से कम हो जाएगा। इसके अलावा, कार्यक्रम स्थल के भीतर अपेक्षाकृत ठंडा वातावरण बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में डेजर्ट कूलर लगाए जा रहे हैं।

तमिलनाडु में भाजपा के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद : चिदंबरम

नईदिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने विश्वास व्यक्त किया है कि डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में पर्याप्त बहुमत से जीत हासिल करेगा और जोर देकर कहा है कि राज्य में भाजपा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष संबोधन में चिदंबरम ने कहा कि भाजपा के लिए द्वार पूरी तरह बंद है। तमिलनाडु की जनता भाजपा को कभी स्वीकार नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तमिलनाडु में कोई साख नहीं है, इसलिए पलानीस्वामी की भी कोई साख नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह की तमिलनाडु में कोई साख नहीं है। गठबंधन के चुनावी रिकॉर्ड पर विचार करते हुए, उन्होंने पिछली जीतों का जिक्र करते हुए कहा कि तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन पिछले चार चुनावों में, जिनमें मौजूदा चुनाव भी शामिल है, आजमाया हुआ है।

यूपी में अखिलेश का वापसी का दावा, भाजपा पर किया अटैक

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी करेगी और उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्षी गठबंधन बरकरार रहेगा। रेवाड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक बना रहेगा, कांग्रेस हमारे साथ होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीटों का बंटवारा चुनावी ताकत के आधार पर होगा, न कि संख्या के आधार पर। उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुद्दा सीटों की संख्या नहीं है; मुद्दा जीतने की क्षमता है। जो जीत सकते हैं, उन्हें टिकट मिलेगा। भाजपा को निशाना बनाते हुए यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है कि जो सदन (संसद) में हारता है, वह बाहर भी हारता है।

हेमंत सोरेन का विमान न उतरने देने पर भड़की टीएमसी

अलाप्पुझा। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन को झाड़ग्राम में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर आरोप लगाया कि यह फैसला उस समय लिया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाड़ग्राम में मौजूद थे और उन्होंने अपना कार्यक्रम बढ़ा दिया था। पार्टी ने इसे आदिवासी-विरोधी मानसिकता करार दिया और कहा कि यह आदिवासी नेताओं के साथ भेदभाव है। टीएमसी ने अपने बयान में कहा कि दोनों नेता लोकतांत्रिक रूप से चुने गए हैं, फिर भी उन्हें घंटों इंतजार कराया गया और बाद में उन्हें रांची लौटने को मजबूर होना पड़ा। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी लोगों का अपमान किया है।

पटना में एनडीए का महिला आक्रोश मार्च

आरक्षण को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना

पटना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक की विफलता के विरोध में सोमवार को पटना में %जन-आक्रोश महिला पदयात्रा% का आयोजन किया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला सशक्तिकरण के प्रति विपक्ष की प्रतिबद्धता की कमी की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि राजनीतिक अवसर कुछ ही परिवारों तक सीमित क्यों हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ जाता। बिहार की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए चौधरी ने बताया कि वर्तमान में बिहार विधानसभा में केवल 29 महिला विधायक हैं।

चौधरी ने आगे कहा कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता, तो कम से कम 122 विधायक होतीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2006 में एनडीए सरकार द्वारा पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के बाद से महिलाओं की चुनावी भागीदारी उम्मीदों से कहीं अधिक रही है। चौधरी ने जमीनी स्तर पर आरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता को रेखांकित करते हुए कहा कि आज बिहार में 50 प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन 59 प्रतिशत से अधिक महिलाएं चुनाव जीत रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस कानून से संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ जाता।

चौधरी ने विपक्षी नेताओं पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि वे चुनिंदा रूप से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके अपने घर की बेटी सांसद बन जाती है तो वे खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरे घर की बेटी को यह मुकाम हासिल करते देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके जवाब में, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री की विधेयक पर की गई टिप्पणी की आलोचना की। यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर परिसीमन को आगे बढ़ाने के बहाने के रूप में विधेयक का उपयोग करने का आरोप लगाया।

तमिलनाडु कांग्रेस चीफ पर आईटी रेड

हार के डर से कर रही भाजपा अत्याचार : स्टालिन

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने राज्य विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष को दबाने की रणनीति के तहत तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगई के आवास पर कार्रवाई की। स्टालिन ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए तमिलनाडु एनसीसी प्रमुख के खिलाफ की गई कार्रवाई को षड्यंत्र करार दिया और भाजपा पर हार के डर से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया।

स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु अध्यक्ष भाई सेल्वा पेरुंथगई के अभियान को चुप कराने के षड्यंत्र की कड़ी निंदा! यह भूलकर कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चुनाव प्रचार समाप्त होने में केवल 48 घंटे शेष हैं, भाजपा सरकार, हार के डर से एकजुट होकर, विपक्ष को दबाने के लिए अत्याचार कर रही है। तमिलनाडु की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इससे पहले के. सेल्वापेरुंथगई ने आरोप लगाया था कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने उनके आवास पर छापा मारा और तलाशी के बहाने उन्हें श्रीपेरुम्बुदुर विधानसभा क्षेत्र में गैरकानूनी रूप से कैद कर लिया, जिससे उन्हें अपने राजनीतिक कर्तव्यों का पालन करने और जनता से जुड़ने से रोका गया।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के दौरान उनके घर के बाहर हिंदी भाषी आयकर विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी ने उन्हें राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका। सेल्वपेरुंथगई ने इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और दावा किया कि उनके मित्रों, रिश्तेदारों और डीएमके पदाधिकारी पद्दई मनोगर के आवासों पर भी तलाशी ली गई। उन्होंने इन कार्रवाइयों को अन्यायपूर्ण बताया और इनकी कड़ी निंदा की। सेल्वापेरुंथगई ने भाजपा और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (एआईएडीएमके) पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

अखिलेश ने महिला आरक्षण पर बोला झूठ?

- ओपी राजभर बोले- भाजपा को क्रेडिट मिलने का था डर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर महिला आरक्षण संबंधी 131वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राजभर का दावा है कि उन्होंने विधेयक का विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिलेगा। एएनआई से बात करते हुए राजभर ने कहा कि इसमें क्या साजिश थी? वह झूठ बोल रहे हैं। भाजपा महिलाओं को 33त्न आरक्षण देने को तैयार है। उन्हें लगा कि इसका श्रेय भाजपा को मिलेगा। इसीलिए वे इसका विरोध कर रहे थे।

इससे पहले, अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को खोखला बताया था। यादव ने स्पष्ट किया कि कोई भी विपक्षी दल महिला विधायकों के लिए आरक्षण का विरोध नहीं करता है और उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को भी आरक्षण योजना में शामिल करने की मांग की। रविवार को रेवाड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। कोई भी विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान, उत्तर प्रदेश में कई लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री भाजपा से भावी महिला प्रधानमंत्री का नाम लेंगे, लेकिन संबोधन खोखला साबित हुआ और उससे जगी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं।

उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई विरोध नहीं है। हमारा मानना ??है कि अगर आप आधी आबादी का सम्मान कर रहे हैं, तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल को महिला आरक्षण विधेयक को रोकने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा था कि सरकार के प्रयासों के बावजूद उनके विरोध ने महिलाओं के सपनों को कुचल दिया है।

जयराम रमेश ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल

असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं परिसीमन था

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र को लोकतंत्र, संविधान और संघीय ढांचे की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस सत्र में बुलडोजर राजनीति और परिसीमन की राजनीति को हार का सामना करना पड़ा। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन था।

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 22 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से पारित हुआ था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। अब 16 अप्रैल की रात अचानक इसे अधिसूचित किया गया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों थी और इसके पीछे क्या मंशा है।

जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या 543 है, लेकिन संवैधानिक विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि राज्यों की हिस्सेदारी अनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने सदन में यह बात कही, लेकिन बिल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में सरकार की नीयत पर भरोसा करना मुश्किल है।

कांग्रेस नेता ने जातिगत जनगणना को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार यह स्पष्ट नहीं कर रही कि जाति जनगणना कैसे कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि असम और जम्मू-कश्मीर में जिस तरह परिसीमन किया गया, वह चिंताजनक है और भरोसा नहीं जगाता। उन्होंने पूछा कि सरकार जाति जनगणना से आखिर क्यों भाग रही है।

रमेश ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं मूर्ख नहीं हैं, वे सब कुछ समझती हैं। उन्होंने कहा कि आज पंचायतों और नगर निगमों में 15 लाख महिला प्रतिनिधि हैं और यह भाजपा की वजह से नहीं, बल्कि कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के पक्ष में रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वर्ष 2029 से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाए और इसमें ओबीसी व आदिवासी महिलाओं को भी शामिल किया जाए। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा महिलाओं के अधिकारों से ज्यादा भाजपा के सत्ता में बने रहने और राजनीतिक संरक्षण का विषय बन गया है।

खेल
प्रमुख समाचार

हॉकी इंडिया ने अंडर-18 के लिए 84 खिलाड़ियों का किया ऐलान

नईदिल्ली। हॉकी इंडिया ने अंडर-18 नेशनल कोचिंग कैंप के लिए कुल 84 खिलाड़ियों (42 पुरुष और 42 महिला) की घोषणा की है। यह कैंप स्पोर्टस् अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल में आयोजित किया जाएगा। खिलाड़ियों का चयन हाल ही में हुए सब-जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है।

यह कैंप जापान में होने वाले अंडर-18 एशिया कप 2026 की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। एक हफ्ते के मूल्यांकन के बाद 42-42 खिलाड़ियों की सूची को घटाकर 24-24 खिलाड़ियों तक किया जाएगा, जो आगे के ट्रेनिंग ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। यह प्रक्रिया अंतिम टीम चयन के लिए महत्वपूर्ण होगी।

कैंप का सबसे खास हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्सपोजर सीरीज होगी, जहां भारतीय पुरुष और महिला -18 टीमें 11 से 21 मई के बीच मुकाबले खेलेंगी। इन मैचों से खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिलेगा और एशिया कप से पहले उनकी तैयारी मजबूत होगी।

महिला टीम की जिम्मेदारी पूर्व कप्तान रानी रामपाल संभालेंगी, जबकि पुरुष टीम को सरदार सिंह और कोच राजनिश मिश्रा ट्रेनिंग देंगे। दोनों ही कोच युवा खिलाड़ियों को आधुनिक हॉकी के हिसाब से तैयार करने पर जोर देंगे।

सरदार सिंह ने कैंप को लेकर कहा, यह हॉकी इंडिया की शानदार पहल है। हमारा फोकस खिलाड़ियों के बेसिक्स मजबूत करने और उन्हें आधुनिक हॉकी की रणनीतियों से परिचित कराने पर रहेगा। इस ग्रुप में काफी टैलेंट है और आने वाले 10-15 साल में यही खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खिलाड़ियों के लिए बड़ा अनुभव साबित होंगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 26 अंक चढ़ा निफ्टी 24364 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में बढ़त के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन यानी सोमवार (20 अप्रैल) को सपाट रुख के साथ खुले। हालांकि, सपाट शुरुआत के बाद बाजर में थोड़ी बढ़त देखने को मिली। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। इस बीच, ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की तरफ से ईरान के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को जब्त किए जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ गया। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 78,632 अंक पर खुला। सुबह 9:30 बजे यह 166.31 अंक या 0.21 फीसदी की बढ़त के साथ 78,659.85 पर ट्रेड कर रहा था। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सोमवार को 24,391.50 पर खुला। सुबह 9:32 बजे यह 13.35 अंक या 0.05 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 24,393 पर ट्रेड कर रहा था।

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

नईदिल्ली। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना ने ईरानी-झंडे वाले टैंकर को जब्त कर लिया है। इस घटना के बाद ईरान की सेना ने त्वरित प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के सरकारी चैनल पर जारी बयान में इस कार्रवाई को युद्धविराम समझौते का उल्लंघन और समुद्र में डकैती जैसा कृत्य बताया गया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल दर्ज की गई है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में कारोबार फिर से शुरू होने पर अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 6.4 फीसदी बढ़कर 87.88 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई। अंतरष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत 6.5 फीसदी बढ़कर 96.25 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। दरअसल, ईरान और अमेरिका के बीच गतिरोध के कारण ईंधन लदे टैंकर होर्मुज के रास्ते गुजर नहीं पा रहे।

दिल्ली में वाहन चलाना महंगा नया नियम लाग

नईदिल्ली। दिल्ली में एंट्री करने वाले कमर्शियल वाहनों को अब अधिक चार्ज देना होगा। दरअसल, दिल्ली नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क बढ़ा दिया है। नए आदेश के मुताबिक 19 अप्रैल से हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए शुल्क पहले के 1,400 रुपये से बढ़ाकर लगभग 2,000 रुपये कर दिया गया है। भारी वाहनों के लिए भी शुल्क में ट्रकों का प्रवेश शुल्क 2,600 रुपये से बढ़कर 4,000 रुपये हो गया है। कुल मिलाकर, कई कैटेगरी के कमर्शियल वाहनों के लिए पर्यावरण नियंत्रण शुल्क में लगभग 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नगर निगम ने टोल प्लाजों को संशोधित शुल्क लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस कदम से परिवहन और रसद लागत पर सीधा प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

जनवरी-जून में 11-13% ऋण वृद्धि की संभावना

नई दिल्ली। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत का बैंकिंग क्षेत्र जुझारू या मजबूत बना हुआ है और ज्यादातर बैंकरों ने जनवरी-जून, 2026 के दौरान गैर-खाद्य ऋ्रण में 11-13 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। रविवार को जारी फिक्की-आईबीए बैंक सर्वेक्षण में यह बात कही गई। यह सकारात्मक रुझान सुधरते बही-खाते, स्थिर आर्थिक गतिविधियों, खुदरा और एमएसएमई ऋ्रण की मजबूत गति और निजी पूंजीगत व्यय में सुधार के शुरुआती संकेतों पर आधारित है। इसके विपरीत, औद्योगिक ऋ्रण वृद्धि की रफ्तार मध्यम रहने की उम्मीद है, जो क्रमिक सुधार को दर्शाती है। बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण क्षेत्रों और सरकार की अगुवाई वाले पूंजीगत व्यय से निवेश गतिविधियां स्थिर रहने की उम्मीद है।

आर्टेमिस-2 से अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया दौर शुरू हो चुका है

सर्गे श्मेमैन

किसी भी बड़े रोमांच की तरह, खासकर ऐसे रोमांच की, जिसे हम पल-पल, हर कदम पर देख सकते हैं, आर्टेमिस-द्ध्द्ध की उड़ान एक बेहद रोमांचक अनुभव रही है। होज, उपकरणों और बोल्ट से भरा वह तंग केबिन; दूर से दिखती छोटी, नीले-सफेद रंग की पृथ्वी की झलकियां; अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच के हवा में लहराते बाल; और यह एहसास कि विशाल तथा जोखिम भरे अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया दौर शुरू हो चुका है, ये सभी मिलकर हमारे मन में विस्मय और उल्लास की ऐसी भावना जगाते हैं, जिसकी हमें इस समय बेहद जरूरत है। पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उस आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता, जो लगातार मेरे कानों में फुसफुसाती रहती है, 'लेकिन हां, हम पहले भी वहां जा चुके हैं।' मैं उस पीढ़ी का बुजुर्ग हूं, जिसके लिए जुलाई 1969 में चांद पर पहली बार कदम रखना एक ऐसा जीवन बदल देने वाला अनुभव था, जिसका महत्व आज से कहीं ज्यादा गहरा था।

अपोलो 11 से पहले, किसी खगोलीय पिंड पर इन्सान के कदम रखने की बात तो बस जूल्स वर्न के उपन्यासों या मार्वल के कार्टूनों में ही सुनने को मिलती थी। फ्लाइ मी टू द मून फ्रैंक सिनात्रा का एक प्रेम गीत था, और उस समय तक होम कंप्यूटर आए भी नहीं थे। 57 साल और कई पीढ़ियों की तकनीकी प्रगति के बाद, उस असाधारण घटना को दोहराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओक्लाहोमा की एक गर्म और सूखी रात में, जब मैं दागों से भरे चांद को निहार रहा था, तब मुझे आज भी वही हैरानी याद आती है-मैं सोच रहा था कि सच में वहां ऊपर दो लोग मौजूद थे। मशहूर न्यूज एंकर

वॉल्टर क्रोनकाइट ने याद करते हुए बताया कि वह इसे बयां करने के लिए शब्द ही नहीं ढूंढ पा रहे थे। आज भी इसके लिए सही शब्द ढूंढना मुश्किल है। उस समय का माहौल बिल्कुल ही अलग था। चांद तक पहुंचने के लिए जिस विस्तृत कंप्यूटिंग की जरूरत थी, वह लगभग किसी चमत्कार जैसी ही अद्भुत लगती थी। उस समय मुझे फोर्ट सिल में एक शुरुआती मिलिट्री कंप्यूटर पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसे 'फील्ड आर्टिलरी डिजिटल ऑटोमैटिक कंप्यूटर' या एफएडीएसी कहा जाता था। इसका वजन लगभग 200 पाउंड था और तोपखाने के निशाने तय करने के लिए इसे एक अलग से जनरेटर की जरूरत पड़ती थी। आज, शायद इसकी जगह एक आइपैड ले सकता है।

यह सच है कि लोगों को अंतरिक्ष में भेजना कोई नई बात नहीं थी। यूरी गागरिन अपोलो 11 से आठ साल पहले ही अंतरिक्ष में जा चुके थे। इसके बावजूद किसी ने नहीं सोचा था कि इन्सान सच में चांद पर खड़े दिखेंगे और उनके पीछे छोटी-सी गोल पृथ्वी संगमरमर जैसी नजर आएगी। चांद पर पहली बार उतरने की घटना पर द टाइम्स के लिए अपनी जबर्दस्त मुख्य रिपोर्ट में, 'मैन वॉक ऑन द मून' जैसी विशाल सुर्खियों के नीचे, विज्ञान लेखक जॉन नोबल विल्फोर्ड ने उस हैरानी और अविश्वास की भावना का वर्णन किया, जो कई लोगों ने महसूस की थी।?उन्होंने कहा था, 'पृथ्वी पर मौजूद लोगों को कीड़े जैसे दिखने वाले लूनर मॉड्यूल और उसके आसपास घूमते इन्सानों की ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन तस्वीरें इतनी साफ और स्पष्ट लगीं कि वे अवास्तविक-सी प्रतीत हुईं। वे उन्हें इन्सानों के बजाय, किसी खिलौने और खिलौने जैसी आकृतियों की तरह ज्यादा लगीं, जबकि वे अब तक की सबसे साहसी और दूरगामी मुहिम पर निकले हुए असली इन्सान थे।' आजकल एक साजिश वाली बात भी फैल रही है कि नासा ने 1969 से 1972 के बीच अपोलो मिशन के तहत छह बार चांद पर इन्सानों को उतारने का जो दावा किया, उनमें से कुछ या शायद सभी लैंडिंग असली नहीं, नकली थीं।

मुझे पता है, यह थोड़ा अहंकारी और अन्यायपूर्ण है कि हम यह जताएं कि हमने तो यह सब पहले ही देख रखा है। असल में, आर्टेमिस-द्ध्द्ध मिशन अंतरिक्ष खोज के नए दौर की शुरुआत है, जिसमें आगे चलकर चांद पर इन्सानों का ठिकाना बनाना और

लेंसकार्ट ड्रेस कोड विवाद : कर्मचारियों को तिलक लगाकर बांधा कलावा

हिंदू संगठन ने स्टोर्स में जाकर किया विरोध प्रदर्शन

बिलासपुर। देश के अलग-अलग हिस्सों में चश्मा कंपनी लेंसकार्ट के ड्रेस कोड विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी विरोध की तस्वीरें सामने आईं, जहां भगवा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग-अलग स्टोर्स पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जताई।

भगवा ब्रिगेड का आरोप है कि लेंसकार्ट के मालिक पीयूष बंसल द्वारा भारत में संचालित लेंसकार्ट की सभी दुकानों में हिंदू धर्मावलंबियों को तिलक, कलावा, बिंदी एवं मंगलसूत्र पहनने से मना किया जा रहा है। जबकि अन्य समाज (मुस्लिम समाज) के लोगों को हिजाब और बुर्का पहनने से मना नहीं किया जा रहा है।

इसी के विरोध में आज भगवा ब्रिगेड के लगभग 20 की संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा बिलासपुर शहर में संचालित लेंसकार्ट के सरकंडा, व्यापार विहार एवं मुंगेली नाका चौक स्थित दुकानों में जाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को तिलक लगाकर एवं कलावा बांधा गया। वहीं विरोध प्रदर्शन के माध्यम से आगामी समय में इस प्रकार के निर्देशों को वापस नहीं लेने पर दुकानों में तालाबंदी किए जाने की चेतावनी दी गई। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा पियूष बंसल पर देश में कठमुल्लों को प्रश्रय दिए जाने जैसी बातें भी कही गईं।

वहीं इस पूरे विवाद के बीच कंपनी पहले ही अपनी सफाई दे चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ङ्ग' पर जारी बयान में कंपनी ने कहा कि हमने आपकी बात सुनी है। साफ़-साफ़ और खुले तौर पर। पिछले कुछ दिनों में हमारे समुदाय और ग्राहकों ने अपनी बात रखी है और हमने उसे ध्यान से सुना है। आज हम अपने 'इन-स्टोर स्टाइल गाइड' को मानकीकृत (स्टैंडर्डाइज़) कर रहे हैं और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक रूप से साझा कर रहे हैं।

कंपनी ने आगे स्पष्ट किया कि गाइडलाइंस स्पष्ट रूप से और बिना किसी दुविधा के हमारे टीम के सदस्यों द्वारा अपनाए जाने वाले हर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक का स्वागत करती हैं—जैसे बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब, पगड़ी और भी बहुत कुछ। इन्हें अपवाद के रूप में नहीं, बल्कि हमारी पहचान के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है।

कंपनी ने यह भी कहा कि यदि किसी कर्मचारी या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो इसके लिए उसे खेद है। साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में सभी नीतियां समानता और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित होंगी।

रामअवतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को कोई राहत नहीं

■ अगली सुनवाई 23 अप्रैल को

रायपुर। नई दिल्ली। रामअवतार जग्गी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए हुए अमित जोगी को सोमवार दोपहर 12 बजे दो जजों की बेंच के सामने की गई अपील पर कोई राहत नहीं मिली है और माननीय न्यायाधीश महोदय ने इस मामले पर 23 अप्रैल को सुनवाई का फैसला लिया है।

अमित जोगी की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई गई। एक याचिक एक जज के चैंबर में लगाई गई जो कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सरेंडर करने पर स्थगन के लिए थी। दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट के दो नंबर कोर्ट में लगाई गई थी जिस पर दो जजों ने आज सुनवाई की और यह तय किया गया कि 23 अप्रैल, गुरुवार को इस मामले को आगे सुना जाएगा। अदालत में मृतक रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी के वकील भी खड़े हुए थे। इस बेच ने सरेंडर करने से किसी रियायत देने से मना कर दिया और कहा कि जिस जज के चेंबर में यह आवेदन लगाया गया है वही इसका फैसला करेंगे।

उल्लेखनीय हैं कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को दोषी ठहराया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के 31 मई 2007 के फैसले को पलट दिया। अदालत ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अमित जोगी को तीन सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में सरेंडर नहीं करने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक ही साक्ष्य के आधार पर कुछ आरोपियों को दोषी ठहराना और मुख्य साजिशकर्ता को बरी करना न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को साक्ष्यों के विपरीत और त्रुटिपूर्ण बताया।

पर्यटन एवं संस्कृति अग्रवाल ने 'श्री अग्रोहा पैलेस' का किया भूमिपूजन

150 अत्याधुनिक कमरों सहित भव्य परिसर से मध्य भारत में बनेगी नई पहचान

■ सेवा और सामाजिक चेतना का बनेगा नया केंद्र

रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर में प्रस्तावित 'श्री अग्रोहा पैलेस' का विधिवत भूमिपूजन कर आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परम पूज्य महाराजा अग्रसेन जी के वंशज होने का गौरव केवल हमारी पहचान नहीं, बल्कि एक पुनीत उत्तरदायित्व भी है। सेवा, त्याग और लोकमंगल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह परियोजना समाज के सामूहिक संकल्प और सहभागिता का प्रतीक बनेगी।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि किसी भी भवन की सार्थकता केवल उसके भौतिक स्वरूप में नहीं, बल्कि उसमें निहित सेवा भावना और समाज के प्रति समर्पण में होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि समस्त समाज के सहयोग से निर्मित 'श्री अग्रोहा पैलेस' आने वाले समय में जनसेवा, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि यह भव्य परिसर 150 अत्याधुनिक कमरों, विशाल हॉल तथा सर्वसुविधायुक्त लॉन से सुसज्जित होगा, जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा।

इस अवसर पर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अग्र समाज का इतिहास सेवा, समर्पण और लोककल्याण की गौरवशाली परंपरा से परिपूर्ण रहा है। हमारे पूर्वजों ने धर्मशालाएं, बावड़ियां और अन्न क्षेत्र बनाकर मानवता की सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी भवन केवल ईंट-पत्थरों से नहीं, बल्कि उसमें समाहित भावना, सहभागिता और सेवा के भाव से जीवंत बनता है।

सांसद श्री अग्रवाल ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे इस प्रकल्प को सफल बनाने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति को भी जोड़ें। साथ ही उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा, जरूरतमंद मरीजों के उपचार और बेटियों के सम्मानजनक विवाह में सहयोग देने का संकल्प लेने की अपील की, ताकि 'श्री अग्रोहा पैलेस' वास्तव में समाज सेवा का जीवंत केंद्र बन सके।

कार्यक्रम में अग्रवाल सभा अंबिकापुर के अध्यक्ष श्री संजय मित्तल, श्री अजय अग्रवाल, श्री बाबूलाल गोयल, श्री योगेश अग्रवाल, श्री विनोद, श्री कृष्ण कुमार, श्री मनोज जैन सहित समाज के अनेक गणमान्य एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

पोषण 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन से ही कुपोषण पर लगेगा निर्णायक अंकुशः डॉ. रेणुका श्रीवास्तव

रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने आईसीडीएस अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रमों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रगति तथा जमीनी स्तर की चुनौतियों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में सुपोषण अभियान के तहत जारी फंड एवं उससे संबंधित समस्याओं पर विशेष चर्चा करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन तथा मानदेय भुगतान की स्थिति की जानकारी ली गई। संचालक ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में आवंटित राशि का समयबद्ध एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

संचालक डॉ श्रीवास्तव ने 100 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु जारी आवंटन एवं व्यय की समीक्षा करते हुए निर्माण और संचालन कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी लेते हुए रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सेक्टर पर्यवेक्षकों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के यात्रा भत्ता भुगतान की स्थिति पर भी चर्चा की गई। संचालक ने भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित राशि के उपयोग की समीक्षा करते हुए वर्ष 2026-27 के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कुपोषण उन्मूलन के लिए सभी जिलों को लक्ष्य आधारित कार्य करना होगा।

बैठक में सुपोषण योजना के तहत पोर्टल एंट्री कार्य की समीक्षा करते हुए डेटा एंट्री को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सैनिटरी वेंडिंग मशीन एवं इंसिनरेटर मशीन के स्थापना एवं सुधार कार्यों के लिए आवंटित राशि के उपयोग पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

वजन मशीनों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को आवश्यक उपकरणों को सुचारू रूप से संचालित रखने के निर्देश दिए गए।

संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम हितग्राही तक पहुंचे, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग, जवाबदेही और फील्ड स्तर पर सक्रियता बेहद आवश्यक है। उन्होंने सभी अधिकारियों को समय-सीमा में लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी और संचालनालय के अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग के अतिरिक्त पीठ का उद्घाटन

रायपुर। रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग के अतिरिक्त पीठ का आज अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हितों की रक्षा और न्याय की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारा सर्वोच्च उद्देश्य है। उन्होंने इस अतिरिक्त पीठ की स्थापना को उपभोक्ता मामलों के शीघ्र निपटारे की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया।

जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर की अतिरिक्त पीठ के अध्यक्ष का दायित्व प्रशांत कुंडु और सदस्य का दायित्व आनंद वर्गीस को सौंपा गया है। सोमवार से ही मामलों की सुनवाई आज से शुरू कर दी गई है। न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री साव, मंत्री दयालदास बघेल और विभागीय सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि यह अतिरिक्त पीठ उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य प्रमोद वर्मा, रजिस्ट्रार श्रीनिवास तिवारी, जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर के अध्यक्ष डी पी शर्मा, सदस्यगण निरूपमा प्रधान और अनिल अग्निहोत्री उपस्थित रहे।

तेंदुलकर से मिलने वालों की सूची में दिव्यांग छात्र शामिल

रायपुर। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के दंतेवाड़ा प्रवास को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। उनके चाहने वाले उनसे मिलने के लिए छिंदनार पहुंचेंगे, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रखी गई है। मिलने वालों की सूची पहले से तैयार कर ली गई है और केवल चयनित लोगों को ही मुलाकात का मौका मिलेगा। इसी सूची में सक्षम स्कूल जवांगा में 11वीं कक्षा में पढने वाले दिव्यांग छात्र मडड़ाराम का नाम भी शामिल है। उसके साथ दो अन्य दिव्यांग छात्र भी सचिन से मुलाकात करेंगे। मडड़ाराम इस खास मुलाकात को लेकर बेहद उत्साहित है। उसने सचिन से पूछने के लिए सवाल भी तैयार किए हैं। वह जानना चाहता है कि सचिन क्रिकेटर कैसे बने, उन्हें प्रेरणा कहां से मिली और दिव्यांग होने के बावजूद वह क्रिकेट में आगे कैसे बढ़ सकता है। मडड़ाराम वही बच्चा है, जिसका क्रिकेट खेलते हुए वीडियो कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। साल 2020 में सचिन तेंदुलकर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि यह उनके दिल को छू गया। उन्होंने लोगों से भी इस प्रेरणादायक वीडियो को देखने की अपील की थी। वीडियो को हजारों लोगों ने पसंद किया और देशभर में मडड़ाराम की चर्चा हुई।

रेलवे ने स्क्रैप की बिक्री से 6813.86 करोड़ की कमाई की

रायपुर/बिलासपुर। भारतीय रेलवे, स्क्रैप से होने वाली निरंतर आय और गैर-किराया राजस्व स्रोतों में लगातार वृद्धि की मदद से यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाते हुए अपनी वित्तीय स्थिरता को मजबूत कर रहा है और यह सभी सुविधाएं बिना यात्री टिकट किराए बढ़ाए मुमकिन हो पा रही हैं।

निष्क्रिय संपत्तियों से मूल्य प्राप्त करके और किराए के अलावा अन्य नए राजस्व स्रोतों का विस्तार करके, रेलवे यह सुनिश्चित कर रहा है कि स्टेशन पर सुविधाओं, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं और यात्री सुविधाओं में सुधार वित्तीय रूप से टिकाऊ तरीके से हासिल किए जाएं। यह संतुलित दृष्टिकोण कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन, ग्राहक-केंद्रित निवेश और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं पर रणनीतिक फोकस को दर्शाता है, जो अधिक आरामदायक, आधुनिक और विश्वसनीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए रेलवे की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। भारतीय रेलवे ने स्क्रैप निपटान में एक अहम उपलब्धि हासिल की है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया है। 6000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले, रेलवे ने 6813.86 करोड़ रुपए की स्क्रैप बिक्री दर्ज की, जो निर्धारित बेंचमार्क से कहीं अधिक है और उल्लेखनीय दक्षता दर्शाती है।

अनाधिकृत वेंडिंग के खिलाफ वाणिज्य विभाग का अभियान

रायपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं खाद्य प्रदार्थों स्वच्छता एवं गुणवत्ता बनाए रखने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम द्वारा स्टेशनों एवं ट्रेनों में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले अनियमित यात्रियों की जांच की गई तथा उनसे नियमानुसार जुर्माना वसूला गया। साथ ही, स्टेशनों एवं ट्रेनों में अनाधिकृत रूप से वेंडिंग (बिक्री) करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। भविष्य में पुनः इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी के निर्देशन में मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री राकेश सिंह के नेतृत्व में 04 वाणिज्य निरीक्षक एवम 02 टीटीई स्टाफ के साथ आज दुर्ग स्टेशन पर अनियमित यात्रियों एवम अनाधिकृत वेंडिंग के खिलाफ वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल के साथ संयुक्त कार्यवाही के दौरान रेल अधिनियम 144 के तहत 08, 145 क्क के तहत 03, 145 और 147 क तहत 04 एवम 147 के तहत 01 ऐसे कुल 16 लोगों पर कार्यवाही किया गया।

कमल विहार से बुलेट चुराने वाले गिरफ्तार

रायपुर। कमल विहार से बुलेट चुराने वाले गिरफ्तार हो गए है, पुलिस उपायुक्त संदीप पटेल (वेस्ट जोन), अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (वेस्ट जोन) राहुल देव शर्मा एवं सहायक पुलिस आयुक्त न्यू राजेंद्र नगर नवनीत पाटित द्वारा शहर में हो रहे चोरी के घटनाओं में अकुंश लगाने हेतु लगातार थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने एवं संपत्ति संबंधी प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों के तस्दीकी हेतु निर्देश दिया गया है। प्रार्थी योगेश कुमार बांदे द्वारा पुलिस को सूचना दिया की उनके मोटर सायकल बुलेट सीजी 04 एन.डब्ल्यू. 1420 जिसे उनके दोस्त हरीशचंद्र बंजारे चलाते है कमल विहार सेक्टर 04 वेलफेयर सोसायटी के पार्किंग में खडी किया था दूसरे दिन दिनांक 17.04.2026 को आकर देखा तो गाडी वहां नही थी जिसे कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है की रिपोर्ट पर दिनांक 19.04.2026 को अपराध क्रमांक 325/2026 धारा 305, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी थाना टिकरापारा निरीक्षक राजेश कुमार मरई को चोरी गए बुलेट और अज्ञात आरोपी का पता तलाश करने निर्देशित किया गया।

महिला आरक्षण पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हल्लाबोल

परिसीमन का इंतजार क्यों? तुरंत लागू हो पारित हो चुका अधिनियम

रायपुर। महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगा रही है कि वह इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रही है और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण पास नहीं होने के पीछे की वजह बताई।

जीपीएम जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही संसद से पारित होकर कानून बन चुका है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33त्न आरक्षण का प्रावधान है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन को शर्त बनाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा इसी प्रक्रिया के नाम पर देरी कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जा सकता है। इसके लिए मौजूदा सीटों में ही 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है और परिसीमन का इंतजार जरूरी नहीं है।

नारायणपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीवान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन थोपने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि 2023 में कानून बन चुका है, फिर देरी क्यों? 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना गलत है। नई जनगणना (2026-27) और जातिगत जनगणना के बाद ही प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार गंभीर है तो तुरंत आरक्षण लागू करे।

कवर्धा में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण को बार-बार नया मुद्दा बनाकर पेश कर रही है, जबकि यह पहले ही कानून बन चुका है। कांग्रेस ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसका महिला आरक्षण से सीधा संबंध नहीं है। इसे परिसीमन से जोड़कर मुद्दे को टाला जा रहा है। लोकसभा सीटें बढ़ाने और पुराने आंकड़ों के इस्तेमाल पर भी आपत्ति है।

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष द्वारिकाधीश यादव ने कांग्रेस भवन में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के साथ ही यह कानून का रूप भी ले चुका है। हाल ही में 16 अप्रैल 2026 को भाजपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को संसद में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के रुप में पेश किया है। यह विधेयक महिला आरक्षण से सीधे तौर पर संबंधित था ही नहीं।

खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव ने कहा संसद में जो विधेयक गिरा वह लोकसभा परिसीमन की सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की जानी थीं।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इतिहास पर नजर डालें तो पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिलाने की पहल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में की थी। हालांकि वह विधेयक उस समय राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। बाद में 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी।वी। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में यह व्यवस्था लागू हुई, जिससे आज देशभर में लाखों महिलाएं स्थानीय शासन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा, संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए 2010 में भी प्रयास हुए, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था।

कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत उनके शासन काल में हुई थी। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पी।वी। नरसिम्हा राव के योगदान का भी उल्लेख किया गया।

वहीं भाजपा का कहना है कि सही प्रतिनिधित्व के लिए परिसीमन जरूरी है। अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर ही आरक्षण लागू होना चाहिए। कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

महिला आरक्षण, जनगणना और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दों के जुड़ने से यह राजनीतिक बहस आने वाले समय में और तेज हो सकती है। संसद से लेकर जनता तक इस पर चर्चा जारी रहने की संभावना है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.